हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

25 फरवरी, 1986

खण्डड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 25 फरवरी, 1986

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(6)1
पि चमी बंगाल विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का स्वागत	(6)8
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(6)9
वर्श 1986–87 का बजट पे ा करना	(6)23

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 25 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे। श्री ए0सी0 चौधरी।

Raising off Minimum Limit of Gratuity to the Pensioners

***1104. @Sh. A.C. Chaudhry, Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Finance be pleased to state:-

(a) whether the Government is aware of the fact that the Central Government has raised the minimum limit of gratuity from Rs. 36000/- to Rs. 50000/- for its pensioners with effect from 1-4-1985 and the Government of Punjab and Himachal have also adopted the said pattern for their pensioners;

(b) whether it is also a fact that the Haryana Government has adopted the said pattern for its pensioners with effect from 1-1-1986; and

(c) if the reply to part(b) above be in the affirmative, whether there is any proposal under consideration of the

Government to revise its decision and to make it applicable with effect from 1-4-1985 to avoid hardship to its pensioners?

Finance Minister (Sh. Sagar Ram Gupta):

(a) Yes Sir. The State Government is aware of it. The Punjab Government has also done so. Information about Himachal Pradesh Government is not available.

(b) No, Sir.

(c) In view of the reply to (b) above, the question does not arise. However, the whole matter is under consideration of the Government.

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, ये एम्पलाइज पैन ानरज की कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं और इस बारे में सैंट्रल गवर्नमैंट ने पहले ही प्रैसीडैंट बना रखा है। क्या सरकार एम्पलाइज का ध्यान रखते हुए कोई आगामी स्टैप उठाएगी ? दूसरे, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे एम्पलाइज हैं जिनको यह बैनिफिट मिलेगा अगर इस स्कीम को 1—4—85 से लागू कर दिया जाए तथा इस पर कितनी धन रा ि ा लगेगी ?

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, जैसे मैंने अपने रिप्लाई में अर्ज किया है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है। स्पीकर साहब, सैंट्रल गवर्नमैंट ने जो पैन ानरज की ग्रेचुएटी के रूल्ज या सिस्टम बना रखा है, हम उसके मुताबिक अपने रिटायर्ड एम्पलाइज को पहले ही दे रहे है। अब जो उन्होंने किया है हम उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य

को बताना चाहता हूं कि चूंकि इस स्कीम को लागू करने पर तरीबन पांच करोड़ रूपए का खर्चा आएगा इसलिए सरकार को इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत पड़ी है कि इस खर्चे को देने से हमारे दूसरे डिवैल्पमैंट के कामों पर कितना असर पड़ेगा। किस तरीके से उधर से इस अमाउंट को सेव किया जा सकता है, ये सारी बातें सोचने की हैं।

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, मैंने पूछा था कि अगर 1–1–86 की बजाए 1–4–85 कर दिया जाए तो इस गैप को नैरो डाउन करके कितने एम्पलाइज बैनिफिटड होंगे और कितनी रा ि ा खर्च होगी ?

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, फिलहाल 1985 और 16986 के गैप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है, लेकिन मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारा जो पैन् ानरज के ऊपर खर्चा आ रहा है, वह 1984–85 में 19.48 करोड़ रूपए था और 1985–86 में टैंटेटिव 19.83 करोड़ रूपए है। इतना पैसा हर साल हम रिटायर्ड कर्मचारियों पर पहले ही खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर इसको हम मंजूर कर लेते हैं तो 5 करोड़ रूपए सालाना का खर्चा और आएगा।

श्री नेकी रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर कोई एम0एल0ए0 आर्मी से

पैन्‍ ानयाफता है तो क्या सरकार कोई ऐसी सुविधा देने की कोि ाश करेगी कि वह दोनों जगह से पैन्‍ ान लेता रहे ?

श्री अध्यक्षः अगर आप अपने लिए मांगना चाहते हैं तो बता दें। (हंसी)

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, आरमी से रिटायर होने वाले लोगों की पैन्‍ ान का खर्चा तो केन्द्रीय सरकार देती है, राज्य सरकार उनको कुछ फैसिलिटीज जरूर देती हैं। जहां तक एम0एल0एज0 का सवाल है, उसके लिए पैन्‍ ान के रूल बने हुए है। एम0एल0एज0 की पैन्‍ ान अगर बढ़ानी हाउस मुनासिब समझे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि मामला अंडर कंसिड्रे ान है। क्या इस बारे में कोई मीटिंग हुई है कि हम यह पैट्रन अपनाएंगे ?

श्री सागर राम गुप्ताः स्पीकर साहब, स्टेट गवर्नमैंट ने इस महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने के लिए एक कैबेनिट सब कमेटी बनाई हुई है। उसमें मैं मैम्बर हूं, पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर मैम्बर हैं ओर एक्साइज एंड टैक्से ान मिनिस्टर भी मैम्बर है। फाइनैंस सैक्रेटरी उसके सैक्रेटरी है। यह कमेटी इस मामले पर विचार कर रही है।

Branch College for Girls at Narnaul

***1078. @Sh. Nihal Singh:** Will the Minister of State for Education be pleased to state:-

(a) the total number of girl students in the Branch College for Girls of Government College Narnaul as at present;

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the said College a full-fledged Degree College for Girls; and

(c) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) 403.

(b) No.

(c) Question does not arise.

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फुल फलैज्ड कालेज के लिए कितनी लड़कियों का होना जरूरी है। यानी फुल फलैज्ड कालेज खोलने के लिए क्राइटेरिया क्या है ?

श्री जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय क्राइइटेरिया तो वैसे बना नहीं है लेकिन जिस कालेज में अन्दाजन 500 या 700 लड़कियां हों, उसको फुल फलैज्ड कालेज बना देते है। नारनौल के कालेज में करीब तीन हजार बच्चे थे वहां पर लड़कियों का

अलग विंग बना दिया है जिसमें 403 लड़कियां हैं। इनमें से 161 लड़कियां फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। बाकी की ब्रेक–अप इस समय मेरे पास नहीं है।

Construction o a Building for Civil Hospital Karnal

***1100. Bahin Shanti Devi:** Will the Minister of State for Health be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the foundation stone of the building of Civil Hospital, Karnal was laid by the Chief Minister on 31-10-1983;

(b) if so, the time by which the construction of the said building is likely to be started and completed; and

(c) the total amount for the construction of the said building provided or likely to be provided?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी):

(क) जी हां।

(ख) पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर।

(ग) वर्श 1985–86 तक 10.00 लाख रूपये। वर्श 1986–87 में कितनी रा ि ा दी जाने की सम्भावना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना धन उपलब्ध होगा।

बहिन भाान्ति देवी: स्पीकर साहब, जवाब में पूरी जानकारी नहीं दी गई है। इन्होंने 1985–86 तक का 10 लाख

रूपया बताया है। मैंने तो यह भी पूछा था कि यह काम कब खत्म होगा और कितनी रा ि ा अगले बजट में इसके लिए रखी जाएगी ? मैं यह चाहती हूं कि इस हस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द हो इसलिए इसके लिए ज्यादा रा ि ा रख लें।

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, वैसे तो करनाल में इस वक्त दो सौ बैड का हस्पताल है लेकिन पुरानी बिल्डिंग में है। जो जन–गणना 1981 मे हुई थी उसके अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या 13,17,823 थी। उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि इस हस्पताल को 300 बैड का बना दिया जाए। भाहरों के हस्पतालों पर देहात के लोग आने की वजह से बर्डन रहता है इसलिए पलानिंग कमि ान और अपनी सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि पहले प्राथमिक सुविधाएं वहां दी जाएं जहां यह सुविधाएं नहीं है। फिर भी भाहरों के हस्पतालों के लिए हमने माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया था। मुख्य मंत्री जी ने आ वासन दिया था कि सरकार ने जिन हस्पतालों के बारे में आ वासन दिया हुआ है उनको इस वर्श में चालू करवाने के लिए कुछ न कुछ रा ि ा की व्यवस्था जरूर की जाएगी। मैं बहिन जी को बताना चाहती हूं कि करनाल का हस्पताल एकदम तो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि उस पर 362 लाख रूपये के करीब खर्च आएगा। यह रा ि ा एकदम मिलने की संभावना बहुत कम है क्योंकि करनाल की तरह और जिलों के हस्पताल भी है। करनाल का हस्पताल पांच मंजिला बनेगा जिसमें ओ0पी0डी0, इन डोर,

आपरे ान थिएटर तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसको हम अगले वर्श बनाने की कोि ा ा करेंगे।

बहिन भाान्ति देवीः स्पीकर साहब, अब यह हस्पताल 200 बिस्तर का है लेकिन वहां पर 400 से भी ज्यादा मरीज रूके होते हैं। हस्पताल के सभी बररामदे कवर किए हुए हैं। फिर भी मरीज बाकी रह जाते हैं इसके अलावा वहां पर रैड क्रास से चिकें लेकर लगाई गई है। कही मरीज अपना स्वास्थ्य और अधिक खराब न कर लें। यह करनाल मेन रोड पर स्थित है। मेन रोड पर एक्सीडैंटस इतने होते रहते हैं कि रोजाना बहुत से लोग घायल होते हैं उन सबको करनाल के हस्पताल में ही लाया जाता है। इसके अलावा आस पास के बीमार लोग भी लाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में मीरज बाहर पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे हस्पताल की तरफ सरकार को सब से पहले ध्यान देना चाहिए। मैं चाहती हूं कि इस हस्पताल के लिए भाीघ्र अधिक रा ि ा दी जानी चाहिए। यह मानवता की सेवा का काम है।

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, इसमें कोई सन्देह नहीं कि करनाल के होस्पीटल में बैड्ज की जितनी कैपेसिटी है वह मरीजों की तादाद को देखते हुए कम है इसलिए सरकार ने उस होस्पीटल को अपग्रेड करने का फैसला लिया था। मैंने बहन जी को बताया था कि उस होस्पीटल का जो एमरजैंसी वार्ड, आप्रे ान थिएटर और इन्डोर वार्ड बनना है, उनका काम इसी वर्श भाुरू करवा दिया जाएगा। जितनी देर तक एमरजैंसी वार्ड,

आप्रै ान थिएटर और इन्डोर वार्ड बन कर तैयार नहीं होते तब तक पुरानी बिल्डिग मे मरीज दाखिल होते रहेंगे। जिस समय यह पांच मंजिला बिल्डिंग बन कर तैयार हो जाएगी उस समय पुरानी बिल्डिंग को गिरा देंगे और इसी साल वहां पर 100 बैड की बिल्डिंग बना कर तैयार करने का प्रावधान है। इसी तरीके से अगले साल में फेज्ड मैनर में सभी होस्पीटल्ज का काम भुरू करवाएंगे। मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने डिसीजन लिया है कि 30 हजार की आबादी तक एक मोडीफाइड पी0एच0सी0 बनाई जाए और चार पी0एच0सीज0 के ऊपर एक कम्यूनिटी हैल्थ सैंटर बनाया जाए जिससे जो फैसिलिटीज मरीजों को भाहरों के होस्पीटल में मिलती हैं, वह देहातों में ही मिल जाएं।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने करनाल सिविल होस्पीटल की चर्चा करते हुए सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज के होस्पीटल्ज की चर्चा की है। अम्बाला में 200 बैठ का होस्पीटल बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने 1983 में भवन का ि ालान्यास किया था लेकिन आज तक नई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई कार्य आरम्भ नहीं हुआस है। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या इसी वर्श अम्बाला होस्पीटल की बिल्डिंग बनाने के लिए बजट का कुछ हिस्सा लगा कर काम आरम्भ करवाने की कोई योजना है ?

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, जवाब तो मैं दे चुकी हूं लेकिन मैं अपने माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि अम्बाला में होस्पीटल के स्टाफ क्वार्टर्ज बन चुके हैं और सी.एम. साहब उनका उद्घाटन भी कर चुके हैं। यह नहीं कि उस होस्पीटल का काम ही शुरू नहीं हुआ है। होस्पीटल की बिल्डिंग बनाने का काम इसी वर्श शुरू करवाएंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, 1.10.1983 को मुख्यमंत्री महोदय ने करनाल होस्पीटल का शिलान्यास किया था उस वक्त यह घोशणा जरूर की होगी कि या होस्पीटल इतने दिन में बन कर तैयार हो जाएगा। अभी बहिन जी ने बताया कि इस पर 3 करोड़ रूपए खर्च होंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह कितने दिन में बन कर तैयार हो जाएगा? स्पीकर साहब, 1983 के बजट के बाद 1984 का बजट आया। उस बजट में उस होस्पीटल की बिल्डिंग की नींव खुदवाई होगी, उसके लिए लोहा भी खरीदा होगा और ईटें वगैरह खरीदी होंगी। उसके बाद 1985 का बजट आया उसमें बहन जी ने बताया है कि उस होस्पीटल पर 10 लाख रूपए खर्च हुए हैं। मैं बहिन जी से जानना चाहता हूं कि क्या होस्पीटल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम ओरिजनल प्लान में दिए गए टाईम के मुताबिक हो जाएगा और क्या उसी प्लान के मुताबिक काम चल रहा है। You see the construction depends on time and availability of funds.

श्रीमती करतार देवी: स्पीकर साहब, लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ प्लाट बनानी ही पड़ती हैं और उनकी घोशणा भी करनी पड़ती है। इस समय मेरे पाास 1984–85 की फिगर्ज नहीं हैं लेकिन 1985–86 में उस होस्पीटल की कंस्ट्रक्शन पर 10 लाख रूपए खर्च हो चुके हैं। उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का बकाया काम अगले साल जरूर शुरू होगा और चालू रहेगा।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं थोड़ा क्लीयर कर देना चाहता हूं। इसमें जमीन की कुछ दिक्कत आ गई थी क्योंकि जमीन का केस कोर्ट में चला गया था इसलिए इस होस्पीटल को बनाने में देरी हो गई। उस पर 10 लाख रूपए खर्च हो चुके हैं और अगले साल भी इस होस्पीटल को बनाने के लिए कुछ ज्यादा पैसा देने की कोशिश करेंगे ताकि यह होस्पीटल जल्दी से जल्दी बन कर तैयार हो जाए। स्टाफ के रहने के लिए 10 लाख रूपए खर्च करके मकान भी बना दिए हैं और 1986 में उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा देंगे और यह कोशिश करेंगे कि वह होस्पीटल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए।

चौ. कुन्दन लाल: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में मुआना गांव के अन्दर अस्पताल बनाने के लिये 8 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, उस पर कब तक काम शुरू करवा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: जो मेन सवाल है वह करनाल सिविल होस्पीटल के बारे में है गांवों के होस्पीटल्ज के बारे में कोई बात नहीं है। मंत्री जी को गांवों के बारे में इन्फर्मेशन जुबानी याद नहीं रह सकती। आप बैठिए।

श्रीमती करतार देवी: स्पीकर साहब, मुआना गांव के होस्पीटल को बनाने के लिए इस साल काम शुरू करवाने की कोशिश करेंगे।

तारांकित प्रश्न सं. 1097

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य सर्वश्री शिव प्र ाद और फतेह चन्द विज सदन में उपस्थित नहीं थे।

Construction of Residential Colony/Allotment of Plot at Ambala Cantt.

***1901. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for the construction of residential colony at Ambala Cantt. by HUDA for the persons belonging to Scheduled Castes; Backward Classes and Weaker Section of the Society; if so, the number of houses to be constructed; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government for the allotment of

residential plots at Ambala Cantt. to the persons belonging to the categories, as referred to in part(a) above; if so, the number of plots proposed to be reserved for allotment to each of the said categories?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) नहीं।

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के पार्ट (ए) का जवाब दिया है, नहीं लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने सरकार की जमीन दबा कर अपने क्वार्टर्ज बना रखे हैं। वे लोग न सरकारी जमीन का किराया देते हैं और न ही हाउस टैक्स देते हैं। अगर उनकी कालोनी को रैगुलर कर दिया जाए तो उससे सरकार को किराया भी मिलेगा और टैक्स भी मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस जमीन को नोमीनल रेट पर उन लोगों को अलाट करने पर विचार करेगी ताकि सरकार को उसी कीमत भी मिल जाए और वह कालोनी रैगुलर हो जाए।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने नहीं में उत्तर इसलिए दिया हैं क्योंकि अम्बाला कैंट में हुड्डा की कालोनी नहीं है। लेकिन अम्बाला सिटी मे हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है और वहां पर मकान भी बनाए हुए हैं। 1100 परिवारों को उन्होंने मकान दिए हैं। जहां तक लोगों के सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे

का ताल्लुक है, हमारी यह कोि ा ा रहती है कि जिस किसी भाई ने सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है उससे खाली करवाई जाए। इसमें दिक्कत यह आती है कि वे गरीब लोग पिछले 15–20 साल से उस जमीन पर बैठे हुए हैं इसलिए उनको उठाने मे बहुत दिक्कत आती है लेकिन हमने फैसला किया है कि उन लोगों को दूसरी जगह प्लाट दे दिए जाएं और वह जगह खाली करवाई जाए। इसमें दिक्कत यह आती है कि वे गरीब लोग पिछले 15–20 साल स उस जमीन पर बैठे हुए हैं इसलिए उनको उठाने में बहुत दिक्कत आती है लेकिन हमने फैसला किया है कि उन लोगों को दूसरी जगह प्लाट दे दिए जाएं और वह जगह खाली करवाई जाए और दूसरे किसी काम के लिए इस्तेमाल कर ली जाए। उनको रहने के लिए दूसरी जगह दे दी जाए।

पि चमी बंगाल विधान सभा के माननीय अध्यक्ष का स्वागत

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हमें खु ाी है कि आज वैस्ट बंगाल के माननीय अध्यक्ष श्री एच0ए0 हलीम, उनकी सुपुत्री तथा उनके दामाद सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन के वी0आई0पी0 बाक्स में विराजमान हैं। मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सदन की कार्यवाही आ कर देखने का जो उन्होंने कश्ट किया है, उसके लिए मैं एक बार फिर उनका हार्दिक स्वागत तथा धन्यवाद करता हूं।

तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

सेठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, वे लोग अंग्रेजो के जमाने से उस जमीन पर बैइै हुए हैं। वे लोग उस जमीन पर 15–20 साल से नहीं बल्कि 50–60 साल से बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्षः सी0एम0 साहब ने यह कहा है कि जो लोग सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किए हुए हैं उनको दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह देंगे लेकिन वहां पर रैगुलर नहीं किए जाएंगे।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अम्बाला सिटी में जो हासिंग बोर्ड की कालोनी में मकान आलट किए गए हैं, क्या उसमे सरकार की नीति के मुताबिक हरिजनों का 20 परसैन्ट रिजर्वे ान का कोटा पूरा हैं अगर कोटा पूरा नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, हरिजन भाइयों के लिए बाकायदा 19 परसैन्ट रिजर्वे ान हाउस अलाटमैंट में रखी हुई हैं लेकिन हमारे पास इतनी एप्लीके ान्ज नहीं आती, इसलिए जितना उनका कोटा है उतना नहीं दे पाए। लेकिन फिर भी लगभग 749 ि ाड्यूल्ड कास्टस और 218 बैकवर्ड क्लासिज के लोगों को रिहाय ाी मकान अलाट किए हैं।

चौधरी कुन्दन लालः अध्यक्ष महोदय, मै आदरणीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो कमी एप्लीके ान्ज की

ि ाड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज की रह गई हैं, क्या वह पूरी कर ली जायेंगी ?

चौधरी भजन लालः मैंने पहले भी कहा है कि इनकी एप्लीके ान्ज कम आई थीं जिसकी वजह से हम इन लोगों को रिजर्वे ान के पूरे मकान नहीं दे सके। हाउसिंग बोर्ड बाकायदा एप्लीके ान्ज मंगवाता है और रजिस्ट्रे ान करके मकान देता है। इतना ही हीं, हाउसिंग बोर्ड बैकवर्ड क्लासिज, ि ाडयूल्ड कास्टस और जो इकोनोमिकली कमजोर लोग हैं, सबकी एप्लीके ान्ज इन्वाइट करके ही मकान एलाट करता है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल अम्बाला जिले से सम्बन्धित हैं लेकिन मैं आपकी इजाजत से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा और इस हाउस में भी पिछले 3–4 सालों से लगातार यह बात आती रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर और सब–डिवीजनल लैवल पर अन–अथोराइज्ड कलोनाइजर्ज प्लाट काट काट कर बेचते रहे हैं और जिनके खिलाफ बहुत सी एफ0आई0आरज0 दर्ज हैं। इन कलोनाइजर्ज द्वारा गलत प्लाट काटने की वजह से सरकार की जो डिवैल्पमैंट की स्कीमें हैं, वे भी पूरी नहीं हो पातीं, यानी सरकार अपनी स्कीमों को अमली जामा नहीं पहना सकती। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे कलोनाइजर्ज के खिलाफ कड़ी निगरानी रखने के लिए कोई कदम उठाने जा रही हैं ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइवेट कलोनाइजर्ज द्वारा प्लाट बेचने का ताल्लुक है, उसके लिए स्टेट का एक्ट बना हुआ है। एक्ट के मुताबिक अगर कोई प्राईवेट व्यक्ति कालोनीज बनाता है तो उसको सारी जमीन का 45 प्रति ात खाली छोड़ना पड़ता है मान लो किसी ने 100 एकड़ जमीन ली है। उस 100 एकड़ जमीन में से 45 एकड़ जमीन ग्रीन पार्क स्कूल, हस्पताल और खेल के मैदान के लिए छोड़नी पड़ती है। अगर कोई आदमी बिना लाईसैन्स लिए प्लाट काट कर बेचने की कोि ा ा करता है या किसी ने प्लाट बेचे हैं तो सरकार ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए हैं और कार्यवाही की है। यदि किसी मैम्बर साहेबान के नोटिस में ऐसी कोई बात हो तो वे सरकार के नोटिस में लाये, सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगी।

तारांकित प्र न सं0 1105

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री फतेह चन्द्र विज सदन में उपस्थित नहीं थे।

Shortage of Drinking Water in N.I.T. Faridabad

***1130. Sh. A.C. Chaudhry:** Will the Minister of State for Local Govt. be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of drinking water in N.I.T. Faridabad; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to overcome this shortage?

स्थानीय भाासन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रका ा महाजन): हां। एन0आई0टी0 फरीदाबाद में जल वितरण को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की गई है और इसे कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। पानी की सप्लाई आगे और बढ़ाने की संभावना पर अनुसंधान किया जा रहा है।

श्री ए0सी0 चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने फरीदाबाद में पीने के पानी के संकट के बारे में अपनी जानकारी का जिकर किया है, इसकी मुझे बहुत खु ाी हुई। लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां पर पानी की जो कमी है, उसको कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? फरीदाबाद में टयूबवैल्ज की सप्लाई है वहां पर कोई फिल्टर वाटर स्कीम नहीं है। जो ट्यूबवैल्ज इस समय काम कर रहे हैं, वे सिर्फ 15 परसैन्ट ही रिकवायरमैंट पूरी कर पाते है। अब मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद में जल वितरण बढ़ाने के लिए जो एक योजना तैयार की गई है वह कब भाुरू की गई और उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

श्री ओम प्रका ा महाजन: अध्यक्ष महोदय, एन0आई0टी0 सैक्टर 1, 2, 3 और पांच तथा इन्दिरा कालोनी और नई कालोनी में बराबर पानी सप्लाई हो रहा हैं 32 टयूबवैल्ज के जरिए हम वहां पर मीठा पानी सप्लाई कर रहे हैं। इसमें कोई भाक नहीं कि जवाहर नगर और कपड़ा कालोनी जो सन् 1975 में सरकार ने रैगुलर की थी उनको हम मीठा पानी नहीं दे रहे। इसका कारण

यह है कि वहां पर जो 32 टयूबवैल्ज लगे हुए हैं, इनके अलावा 33वां टयूबवैल्ज नहीं लग सकता क्योंकि पानी का लैवल पहले ही नीचे जा चुका है। जो पहले के टयूबवैल्ज लगे हुए हैं उनका पानी भी खराब होना भुरू हो गया है। नहर का पानी वहां पर आ नहीं सकता क्योंकि कोई नहर नजदीक नहीं पड़ती इसमें हमारी सबसे बड़ी मजबूरी यही है कि हम वहां पर और टयूबवैल नहीं लगा सकते। इनको भी याद होगा, जब ये खुद मिनिस्टर थे उस समय एन0आई0टी0 फरीदाबाद को 16 लाख गैलन पानी देने का समझौता हुड्डा के साथ्स सैक्टर 24 तक को देने का हो गया था। हमने वहां पर 75 लाख रूपये की एक स्कीम बना कर और एक और 6 लाख रूपये की स्कीम बना कर पाईप बिछाने का कार्य पूरा कर दिया है। इस तरह टोटल 81 लाख रूपया खर्च हुआ है। हुड्डा वालों ने हमारे से सैक्टर 8 और 9 में पानी सप्लाई करने के लिए 2 टयूबवैल्ज लगाने के लिए 10 लाख रूपया मांगा था जिसमें से हमने 3 लाख रूपया उनको दे भी दिया हैं। वहां पर दो टयूबवैल लग भी गए हैं लेकिन उनको अभी बिजली का कुनैक ान नहीं मिल सका है। यदि बिजली आ जाये तो हम 7 लाख रूपया और खर्च करके और सैक्टर 24 में अपना जनरेटर सैट भी लगा देंगे ताकि उन लोगों को 16 लाख गैलन तक पानी सप्लाई हो सके। इस समय हम इस कालोनी के लिए 35 हजार गैलन पानी ही दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं इन्हें यह भी बताना चाहूंगा कि इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम यमुना नदी बैल्ट पर 'रेनी वैल्ज' लगा रहे हैं। इस स्कीम पर 12 करोड़ रूपये खर्च होने

हैं। 12 करोड़ रूपये में से 6 करोड़ रूपये हम खर्च करेंगे और 6 करोड़ रूपये हुड्डा खर्च करेगा। जब यह स्कीम चालू हो जायेगी तो एन0आई0टी0 फरीदाबाद को 20 साल तो क्या आने वाले 40 सालों तक पानी पर्याप्त रहेगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः अध्यक्ष महोदय, एक स्कीम सन् 1982 में चालू की गई थी। वह स्कीम आज 1986 के आने तक पूरी नहीं हो पाई है मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्शित करना चाहता था। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः इन्होंने आपकी तरफ इ ाारा कर दिया है कि आप भी मंत्री थे। (हंसी)

श्री ए0सी0 चौधरीः मैंने यह इसलिए कहा है कि मैं मंत्री था और मैंने इस समस्या को ट्रू प्रोस्पैक्टिव में देख कर यह स्कीम सन् 1982 में बनवाई थी। मैंने यह स्कीम यह जानकार बनवाई कि कम्पलैक्सिज एडमिनिस्ट्रे ान के पास फाईनांस के रिसोर्सिज कम होंगे और साथ के साथ हुड्डा इसका पार्ट होगा। सरकार और हुड्डा के ज्वायंट एडवेन्चर के रूप में सन् 1982 में यह स्कीम बनाई गई थी। अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को अब वहीं के वहीं देख कर ही मेरा यह सवाल करने का मुद्दा था। आप भी मेरी इस बात को एप्रीि ाएट करेंगे कि इस समय बिजली की बहुत समस्या है। बिजली की समस्या ने पानी की समस्या को और भी एग्रावेट कर दिया है। ये 32 ट्यूबवैल्ज 22 घंटे रोज चल कर

सिर्फ 6, 7 या 8 घंटे ही चल पा रहे है। इस वक्त ठण्ड होने की वजह से वहां पर लोगों ने पानी के बारे में बावेला नहीं मचाया यदि मचाया है तो कम मचाया है। जब आगे गर्मी आएगी तो यह मामला इतना एग्रावेट हो जायेगा कि पब्लिक की रिजेन्टमैंट को रोकना बड़ा मुि कल होगा।

श्री अध्यक्षः आपका सवाल बहुत लम्बा हो गया है। जो आप मेन सवाल पूछना चाहते हो वह पूछ लें।

श्री ए0सी0 चौधरीः मेरा सवाल यह है कि 18 करोड़ 38 लाख रूपये की जो स्कीम ज्वायंट वैंचर मे सन् 1982 में एप्रूवड हुई थी उस पर कब तक काम भाुरू होने की संभावना है और वह कब पूरी होगी ?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं इनके मन की बात समझ गया हूं और इनकी तकलीफ को भी समझ रहा हूं। यदि हमें 16 लाख गैलन पानी मिल जाता है जिसके बारे में मैंने जिकर किया है तो हमारी काफी हद तक पानी की समस्या दूर हो सकती है। हम लोगों को 25 पैसे प्रति हजार लीटर की कीमत पर पानी देते हैं जबकि हुड्डा वाले 85 पैसे प्रति हजार लीटर के हिसाब से सरकार से पैसे मांगते हैं। इतना अधिक रेट हम हुड्डा को दे नहीं सकते थे क्योंकि इससे हमें बहुत अधिक घाटा पड़ता था। इसमें हुड्डा की भी मजबूरी है क्योंकि वह नो प्रोफिट नो लौस पर काम करता है। वह थोड़ा सा डिस्पयूट चल रहा था।

आखिर अब हमने हुड्डा वालों की बात मान ली है। पिछले साल यानी 1985 में हमने हुड्डा के साथ एग्रीमैंट कर लिया है और एक रूपया उन्हौंने मांगा। इस एक रूपये प्रति हजार लीटर देने की बात भी हमने मान ली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इन्हें वि वास दिलाना चाहता हूं कि इसी साल पानी इनको मिल जायेगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा है कि 18 करोड़ 38 लाख रूपये की जो स्कीम सन् 1982 में ज्वायंट एडवेंचर में भ्ारू की गई थी, क्या वह एप्रूव हो गयी है, यदि वह एप्रूव हो गई है तो क्या वह चालू होगी और होगी तो कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, उस स्कीम का सर्वे करवा लिया गया है लेकिन सरकार की कुछ मजबूरियां हैं। सरकार के पास जितने फण्डज होते हैं, उसी के हिसाब से कोई काम करती है। जो 12 करोड़ रूपये की स्कीम है उसमें से 6 करोड़ रूपया हमने देना है और 6 करोड़ रूपया हुड्डा ने देना है। अब हम यह सोच रहे हैं कि पैसे कैसे इकट्ठे किए जायें। मैंने इनसे अर्ज कर दिया है कि फौरी तौर पर इस साल इनकी जो ये दो कालोनीज हैं, उनको पानी दे देंगे। एन0आई0टी0 में और इनके सारे हल्के में पानी जा रहा है। मैंने इनके सारे हल्के का सर्वे किया है। इनके हल्के में एक झाड़सेतली गांव है, जहां का पानी खारा है। वहां हमारी कुछ मजबूरी है। इस गांव के बारे

में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि जब सैक्टर 24 में पानी जायेगा तो वहां पर भी मीठा पानी पहुंचा देंगे। बाकी तकरीबन सारे इनके हल्के में पानी पहुंचा दिया है। बड़खल लेक और अनन्तपुर में भी पानी पहुंचा दिया है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, यह सवाल तो फरीदाबाद के बारे में है लेकिन मैं एक जनरल बात मंत्री जी से जानना चाहता हूं। जिन भाहरों में म्यूनिसिपैलेटीज की स्कीम्ज चल रही हैं और पुरानी जनसंख्या के आधार पर 30 गैलन प्रति व्यक्ति के हिसाब से पानी देने का इन्तजाम किया गया है, क्या वहां बढ़ी हुई जनसंख्या के हिसाब से पानी देने की कोई स्कीम है ताकि लोगों को पूरा पानी मिल सके ?

श्री ओम प्रका I महाजन: अध्यक्ष महोदय, 19 फरवरी को हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें आदरणीय फाईनैंस मिनिस्टर, बहन प्रसन्नी देवी जी और कई ऑफिसर्ज साहेबान थे। उस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि हमारी 17 स्कीम्ज जो पानी के विशय में हैं, यदि उन्हें इम्पलीमैंट कर दिया जाए तो हरियाणा के लगभग उन इलाकों में, जहां पानी की तंगी हैं, काफी राहत मिलेगी। वे स्कीम्ज इसी वर्श पूरी होने जा रही हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी नीचे हैं और खारा है। वहां बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। ऐसी स्कीम्ज को अभी हम पूरानहीं कर पाएंगे।

श्री ए0सी0 चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पंजाबी कालोनी, जवाहर कालोनी और डबुआ गांव की स्कीम्ज के बारे में कल की लिस्ट पर सवाल लगा हुआ हैं और उनके बारे में मैं कल पूछूंगा लेकिन फरीदाबाद के बारे में जो मंत्री जी कह रहे हैं कि पानी पूरा मिल रहा हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि वहां केवल 10 परसैंट से लेकर 15 परसैंट तक पानी मिल रहा है। लोग तीन फुट गहरे खड्डों और नालियों से ईटें लगाकर बालटी और डिब्बों से पानी भर रहे हैं। गर्मियों मे तो हालत और भी खराब होगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि रेनी वैल्ज के ऊपर कप्लैक्स का पैसा लगना है और स्टेट गवर्नमैंट ने उसके लिए कुछ नहीं देना है। इसने तो केवल टैक्निकल और ऐडमिनिस्ट्रेटिव ऐप्रूवल देनी है। 20 रेनी वैल्ज लगने हैं। यदि फिलहाल 4 भी लग जाएं तो काफी राहत लोगौं को मिलेगी और गर्मी के मौसम में उद्धम कम मचेगा।

श्री ओम प्रका ा महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सवाल का दो तीन बार जवाब दे दिया है। सरकार की बिल्कुल क्लीयर इच्छा है कि फरीदाबाद कंप्लैक्स के अन्दर पानी पहुंचे। 35 लाख गैलन पानी इस वक्त हम फरीदाबाद की डेढ़ लाख की पापुले ान के लिए दे रहे हैं। यह पानी 20 गैलन प्रति व्यक्ति बैठता है। नॉर्मज के मुताबिक 10 गैलन प्रति व्यक्ति पानी और दिया जाना चाहिए। लोग गर्मी में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं,

सर्दी में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। रेनी वैल्ज प्रोजैक्ट का काम हम जल्दी ही भुरू करवा देंगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जिन 17 स्कीम्ज का जिकर किया है, वे कहां कहां के लिए हैं ? क्या हांसी का नाम भी इन 17 स्कीम्ज में है या नहीं ?

श्री ओम प्रका ा महाजन: अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं कल बता सकूंगा क्योंकि जबानी मुझे नाम याद नहीं हैं।

चौधरी कुन्दन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सारे हरियाणा की म्युनिसिपैलेटीज में क्या वाटर सप्लाई स्कीम्ज के लिए जैनरेटर्ज लगाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रका ा महाजन: अध्यक्ष महोदय, अभी तो हमने फरीदाबाद कंप्लैक्स के बारे में ही सोचा है बाकी जगहों के बारे में विचार नहीं किया है।

श्री भले राम: अध्यक्ष महोदय, सारे हिन्दुस्तान में पानी पीने वाले हर घंटे में 56 सौ व्यक्ति बढ़ जाते हैं लेकिन पानी उतना ही हैं। क्या सरकार की इस ट्रैन्ड को कम करने की काई नीति है वरना पानी की सारी स्कीम्ज धरी धराई रह जाएंगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): इसके लिए तो आपकी सहायता की जरूरत है। (हंसी)

तारांकित प्र न सं0 1079

यह प्र न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री निहाल सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे।

Government College, Karnal

***1101. Bahin Shanti Devi:** Will the Minister of State for Education be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a building for Government College, Karnal, iff so, thhe time by which it is likely to be started and completed; and

(b) the total amount provided/likely to the provided for the construction of the said building?

Minister of State for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) Yes, The Government have already accepted the proposal to construct new building for Government College, Karnal and necessary administrative approval for teh ssaid purpose has already been issued. The construction work is likely to be started during the corrent financial year and is likely to be completed in a period of about 3 years.

(b) The Government has issued administrative approval for Rs. 13257000/- for this college building. No specific amount is provided separately for a purticular college for construction projects. However, this project is on the priority list of the department and sufficient fuds will be made

available to the PWD under the capital budget over the comming years.

बहिन भाान्ति देवी: क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेगें कि इस भवन का निर्माण कब से भुरू हो जाएगा?

श्री जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, मैने कहा है कि निर्माण कार्य इसी साल यानी 1986–87 मे भुरू हो जाएगा और तीन साल मे पूरा होगा।

श्री भले राम: क्या मंत्री जी बताएगे कि नई बिल्डिंग बनने के बाद पुरानी बिल्डिंग मे लड़कियों का कालेज होगा या कोई और संस्था होगी?

श्री जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, इस बिल्डिंग मे पहले एस.सी.आर.टी. का साईंस विंग था। नई बिल्डिंग बनने के बाद उसमें लड़कियों या लड़कों के स्कूल के लिए विंग खोल दिया जाएगा।

Upgradation of Civil Hospital Ambalal Cantt.

***1092 Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Civil Hospital Ambala Cantt. has been upgranded to 75 Beds and more staff has also been sanctioned therefore;

(b) whether there is also a proposal under consideration of the Government to construct a building for tehextended bed strength of the said Hospital;

(c) whether the necessary funds have been provided for the construction of said building if so, the time by which it is likely to be constructed; and

(d) whether any norm has been fixecd for the allocation of bedsin the Hospital for Urban and, Rural areas according to population, if so, the details thereof?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पूरी बिल्डिंग के लिए धन की व्यवस्था नही की गई हैं लेकिन इसी वर्तमान भवन मे कुद आ यक एडी ान्ज और आल्ट्रै ान करने के लिए लगभग तीन लाख रूपये की रा ि ा का प्रावाधान किया गया है।

(घ) जी नही।

सैठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, (क) भाग के जवाब मे तो इन्होने ''यस'' कहा लेकिन (ग) भाग के जवाब मे ''नो'' कहा। मंत्री महोदया अपनी बात को यह जवाब देकर स्वयं काट रही हैं अगर हस्पताल को अपग्रेड करना है तो फंडज का भी

इन्तजाम होना चाहिए। अगर फंडज का इन्तजाम नही है तो हस्पताल कैसे बनेगा?

श्रीमती करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, यह हस्पताल 100 बैडज का होना हैं। लेकिन धन के अभाव को देखते हुए इसे अभी 75 बैडज का कर रहे है। वर्तमान बिल्डिंग 50 बैडज की है। इसी बिल्डिंग मे एडी ान करने, मोडिफिके ान करने, कुछ कमरों को आपस मे मिलाने और आपरे ान थियेटर आदि बनाने के लिए लगभग तीन लाख रूपये का प्रावधान किया गया हैं।

सैठ राम दास धमीजाः स्पीकर साहब, इन्होने रिटन रिप्लाई मे तो कुद और लिखा हुआ है लेकिन जबानी कुछ और कहा हैं। जब तक पैसा ही नही होगा तो सारी बात होने वाली नही हे। इसके अलावा, स्पीकर साहब, भाहरों के लिए कोई नौर्मज नही हैं। गांव केलिए तो नौर्मज है कि 5 हजार की आबादी पर इतने बैडज का अस्पताल होगा और उससे ज्यादा आबादी के लिए इतने बैडज का हस्पताल होगा। इसी तरह से भाहरों के लिए भी कोई नौर्म होना चाहिए कि डेढ लाख की आबादी के लिए इतने बैडज का हस्पताल होगा।

श्रीमती करतार देवीः सर, इनका सवाल यह था कि क्या अस्पतालों मे बिस्तरों के आबंटन के लिए जनसंख्या के अनुसार भाहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो के लिए कोई नौर्म निि चत किया गया है यदिऐसा हे तो उसका ब्यौरा क्या है? स्पीकर साहब, हस्पताल

मे आने वाले मरीजों के लिए यह नही किया जा सकता कि इतने बैडज भाहरियों के लिए होगें और इतने बैडज गांव वालो के लिए होगे।

चौधरी फूल चन्दः अध्यक्ष महोदय, बड़ी खु ी की बात है कि धमीजा साहब ने भी देहात का जिक्र किया। स्पीकर साहब, देहात के लिए सातवें प्लान मे बहुत सारे सी.एच.सीज., पी.एच. सीज. और सब सैन्टर्ज आदि सरकार ने मंजूर किए है। मेरे क्षेत्र मुलाना के लिए भी मुलाना मे सी.एच.सी. ओर बराड़ा, समलेहड़ी, उगाना, नहोनी और वीटा के लिए प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज मंजूर किए गए हैं। क्या मंत्री जी बताएगें कि इनके निर्माण का काम कब तक चालू कर दिया जाएगा ताकि लोगों को मैडिकल सुविधा प्राप्त हो सकें?

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, जो मिनिमम नीड प्रोग्राम के लिए हमने पैसाा रखा हुआ है, उसके लिए हमने सन् 1990 तक की नीति बनायी हुई हैं। उस निति की सूचना के बारे मे लगभग सभी सदस्यों को पता है कि किन–किन जगहों पर आने वाले साल मे काम भाुरू होगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार हम उन पर काम करवायेगे। उनके लिए धन का कोई अभाव नही है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ः स्पीकर साहब, मै मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि पंचायत से कितना पैसा ओर कितनी जमीन पी.एच.सी. के लिए लेते है। दूसरे जो पी.एच.सी. खोली हुई

है, उन मे भी डाक्टर नही जाते है तो नयी पी.एच.सी. मे भी डाक्टर्ज नही जायेगे? इसलिए मै मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या पूरानी तथा नयी पी.एच.सी. मे डाक्टर्ज भिजवाने का कश्ट करेगी?

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, जहां तक पहले प्र न का सवाल है उस बारे मै बताना चाहूगी कि तीस हजार की आबादीपर हम एक मोडीफाईउ पी.एच.सी. बनाते है। उसके लिए चार एकड़ जमीन मुफ्त देनी पड़ेगी है और पचास हमार रूपयें जमा करवाने पड़ते हैं। यह सभी गांवो के लिए नार्म रखा हुआ हैं। जहां तक डाक्टरों का संबंध है, वेतो हम भर्ती करतै रहते है लेकिन जब हम उनकी अप्वायंटमैंट करते है तो वह गांवो मे जानेसे कुछ संकोच करते हैं। जितने डाक्टर्ज की जरूरत है चाहे उनको पब्लिक सर्विस कमी न के थ्रू या एडहाक बेजिस पर अप्वायंट किया जायें। वे गांवो मे जाना पसन्द नही करते हैं। डाक्टर्ज हमारे पास इतने कम तो नही है, फिर भी देहातो के डाक्टर्ज के कुछ स्थान रिक्त है।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, जैसे वाटर सप्लाई स्कीम के लिए साढे बारह परसैन्ट पैसा गांव वालों का भरना पड़ता है इसी तरह से पी.एच.सी. के लिए पचास हजार रूपया भरना पड़ता है। कई गांवो की पंचायते गरीब होती है, वे इतना पैसा भर नही सकती। जब सरकार की तरफ से 18–20 लाख रूपया लगाना होता है तो पचास हजार रूपया कोई खास बात नही है। वह भी

सरकार अपनी तरफ से लगा सकती हैं। क्या सरकार इस पैसे का न लेने के बारे में गौर करेगी?

श्रीमती करतार देवीः इस पर विचार किया जा रहा है।

चौधरी सूबे सिंह पूनियांः स्पीकर साहब, हम गांवो मे हस्पताल पी.एच.सी. सब – सैन्टर, रूरल डिस्पैन्सरी आदि बनाते जा रहे है लेकिन देहातों मे जो रूरल डिस्पैन्सरीज खोली हुई है, उनकी बिल्डिंग भी बनी हुई है लेकिन वहां ए.एन0एम0, नर्स और उनके काडर का स्टाफ जाना नही चाहते। मेरे हल्कें मे दो गांव ऐसे है जहां पर बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन ए0एन0एम0 नर्स और दूसरा स्टाफ नही पहुच रहा है। क्या सरकार इस स्टाफ को भेजने के बारे मे प्रबन्ध करेगी?

श्रीमती करतार देवीः जिस सब–सैन्अर की बिल्डिंग का जिक्र किया है, भाायद वह खटकड़ गांव की हैं। वहां पर गांव से बाहर बिल्डिंग बनी हुई है। आप जानते हैं कि लड़कियां मैट्रिक पास करने के बाद डेढ सालकी ए0एन0एम0 की ट्रेनिंग लेती है। वे ज्यादातर अन–मैरिड होती है। वे गांवों से बाहर रहने के लिए तैयार नही । हमने पचायत को कहा है कि कही गांव मे रहने को जगह दें दे ताकि वे वहां ठहर सकें।

चौधरी अजमत खांः स्पीकर साहब, बहिन जी ने कहा कि रहने के लिए जगह नही देते है इसलिए वे बाहर रहा पसन्द नही करती। मै किसी दूसरे गांव का जिक्र नही कर रहा मेरे अपने

गांव मलाई मे तीन साल से बिल्डिंग बनी पड़ी है लेकिन वहां पर कोई ए0एन0एम0 नही है। बिल्डिंग टूट गई है। हमने रहने के लिए जगह भी दी लेकिन फिर भी वे नही आती है। मेवात मे काफी जगह ऐसी है जहां पर देहात मे स्टाफ जाने को तैयार नही, क्या सरकार इस तरफ खास ध्यान देगी?

दूसरे मै यह भी जानना चहूंगा कि तीस हजार की आबादी पर चार एकड़ का रकबा और पचास हजार रूपया देना पड़ता हैं। मै आपके जरिए रिक्वैस्ट करूंगा कि इस सिस्टम को बिल्कूल खत्क कर दें। पंचायतो मे जमीन और पैसा न लिया जायें। अगर यही पोजी ान रही तो हमारे इलाके मे अस्पताल नही बन पायेगें।

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, मेवात क्षेत्र मे इस तरह की तंगी जरूर हैं। डाक्टर्ज रूरल एरिया मे जाना पसन्द नही करते है। दूसरे रोहतक, भिवानी, सिरसा से जो लड़कियां ट्रेनिंग ले कर जाती हे, वे वहां जाना पसन्द नही करती। मेवात के लिए हमने उसी एरिया मे ट्रैनिंग पिछले साल मंजूर पवकी थी। लेकिन कोई भी लड़की ट्रेनिंग मे दाखिल होने के लिए नही आयी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उस एरिया मे लड़कियां ि ाक्षित नही हैं। पच्चीस तीस लड़कियों की क्लास वहा चालू की गई थी लेकिन उस एरियां की लड़कियां मिली नही। इस साल आप अपने एरिया की लड़कियों का दाखिल करवां दें, आप को बिल्कूल ब्लैंक चिट दी जाती हैं। अपने एरियाप की लड़कियोंका प्र ि ाक्षण दिलवा

दे ताकि वे उस इलाके मे काम कर सकें। अब ये खुद बता दे इनहोने पिछले साल कितनी लड़कियों का वहा दाखिल करवाया है?

चौधरी कुन्दन लालः क्या मंत्री महोदया बताने को कश्ट करेगी कि जिला जीन्द मे जो हस्पताल सौ बैडज का है उसे दोसौ बैडज का बनाने का विचार है?

(इस प्र न का कोई उत्तर नही दिया गया।)

मास्टर राम सिंहः स्पीकर साहब रादौर पी.एच.सी. मे मैटरनिटी हस्पताल मे कोई भी लेडी डाक्टर नही है। अलहार और बबैन रूरल डिस्पैन्सरीज मे भी कोई डाक्टर नही है। जिस डाक्टर को वहां अप्वायंट किया जाता है, वह छुट्टी ले कर चला जाता हैं मै मंत्री महोदयां से रिक्वैस्ट करूंगा कि वहां पर डाक्टरों का प्रावधान किया जायें और खास तौर पर रादौर मे लेडी डाक्टर को पोस्ट किया जायें।

श्रीमती करतार देवीः स्पीकर साहब, डाक्टर्ज के बारे मे सही फिगर्ज तो इस समय नही दे सकती कि हां पर डाक्टर्ज नही है। आधा जवाब तो इन्होने खुद ही दे दिया कि जिन डाक्टर्ज की पोस्टिंग की जाती है वह वहां जाना पसन्द नही करतें। इसलिए जो जाना नही चाहते उनके स्थान पर हम नयी भर्ती करते है। अगर डाक्टर्ज को मनमाना स्थान मिल जाये तो वे चलें जाते है वरना कोताही करते है।

श्री अमीर चन्द मक्कड़: स्पीकर साहब, जो डाक्टर्ज देहात मे नही जाना चाहते, क्या मंत्री महोदया बतायेगीं कि ट्रेनिंग मे जाने से पहले कोई ऐग्रीमैंट किया जाता है कि इतने दिनों तक सर्विस करनी पड़ेगी?

श्री अध्यक्षः वह तो पहले ही लिखा हुआ हैं।

चौधरी कुन्दन लालः स्पीकर साहब, बहिन जी ने मेरे पहले सवाल का जवाब तो नही दिया लेकिन मेरी कांस्टीच्यूऐसी के मुआना गांव ने आठ एकड़ जमीन और चालीस हजार रूपये पी0एच0सी0 के लिए जमा करवाये हुए है, क्या उस बारे मे बहिन जी बतायेगी कि सरकार ने क्या कदम उठायें है?

श्रीमती करतार देवीः जिन गांवो ने ऐसा किया हे यानी जिन्होन हैल्थ विभाग के नाम जमीन ट्रांसफर कर दी है और पैसे जमा कर दिये है, उन सब गावों मे जल्दी काम भाुरू करने का विचार है?

श्री अध्यक्षः एक बात मै भी पूछ लूं। जो हस्पताल मरीजों के लिए अन–सैफ डिक्लेयर हो गये है और खासतौर पर लेडीज विंग मे, क्या उनके बारे मे भी कुछ बन्दोबस्त करेगी?

श्रीमती करतार देवीः बिल्कूल सर। भााहबाद वाले हस्पताल को हमने कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर रूरल एरियाज मे डाल दिया है औरउस को भी हम बनायेगें।

श्री अध्यक्षः भााहबाद भाहर के हस्पताल का लेडीज विंग अन–सेफ डिक्लेयर कर दिया गया हैं और बन्द पड़ा हुआ हैं। आप जानती है कि वहां पर कितनी बड़ी आबादी है और लेडीज के लिए कोई हस्पताल नही है तो वहा पर कब तक बन्दोबस्त करेगी?

श्रीमती करतार देवीः जैसा कि मैने कहा कि भााहबाद को हमने देहात के साथ कवर किया है और उधर कम्येनिटी हैल्थ सैन्टर मे डाल कर पूरा करने की कोि ा ा कर रहें है।

मुख्यमंत्री (चौधरी भजनलाल): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने कहा कि बड़े भाहरों मे जो हस्पालाल अन–सेफ डिक्लेयर हो चुके है और खासतौर पर लेडीज विंग, ऐसे जितने भी हस्पताल है, उन्हे सरकार सब से पहले बनाने की कोि ा ा करेगी।

सैठ राम दास धमीजाः मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो इन्होने 3 लाख रूपये अलाअ कर रखें है, यह कब तक दे देगे? मै इसके लिये तो इन का अभारी हूं कि इनहोनन अम्बाला केन्ट के हस्पताल कैंट के हस्पताल की बिल्डिंग के लिये कुछ पैसा अलाट किया है। 15 लाख रूपयें देने का वायदा बड़ी मुद्दत के बाद आता है। यह डेट बता दे कि कब तक यह पैसा दे देगें?

श्री करतार देवीः सर, रूपया हमने अलग अलग कामों के लिये नि चित किया हुआ है। जब एक बार फाईनांस

डिपार्टमैंट क्लीयरैंस दे देता है जोकि दी हुई है तो कोई दिक्कत नही है। काम जल्दी ही भ्रारू हो जायेगा।

श्री अध्यक्षः यह तो टाईम पूछ रहे हैं कि कब तक भ्रारू होगा ?

श्रीमती करतार देवीः अब तो अगले साल में भ्रारू होगा।

चौधरी लीला कृ णः स्पीकर साहब, मेरे यहां फतेहाबाद का अस्पताल 60 बैड का हैं। अगर उसमें 100 बैड कर दिये जायें तो उसमें स्पै ालिस्ट डावटर्ज पोस्ट किये जा सकते है। क्या मंत्री जी उस अस्पताल को 100 बैड्ज का करने का प्रवधान करेंगी ताकि लोगों को सुविधा हो सके?

श्रीमति करतार देवीः सर, एक अस्पताल जो अभी अपग्रेड करके 60 बैड का है। अगर उसमें 100 बैड कर दिये जायें तो उसमें स्पै ालिस्ट डाक्टर्ज पोस्ट किये जा सकते हैं। क्या मंत्री जी उस अस्पताल को 100 बैड्ज का कर दिया जाये क्योंकि अभी हमने सारे प्रान्त के देहातों में काफी रूरल हैल्थ सैंटर्ज खोले हैं। इसके अलावा, कुछ देहातों में हमने 10 बैड्ज के अस्पताल भी बनाये हैं ताकि भाहरों पर दबाव कम हो और लोगों को आसानी से इलाज कराने में मदद मिल सके।

चौधरी साहब सिंह सैनीः स्पीकर साहब, मैं भी एक प्र न पूछना चाहता हूं। मेरी कांस्टीच्यूएंसी लाडवा में मुख्य मंत्री

जी गये थे। वहां पर इन्होंने यह ऐलान किया था कि वहां पर 30 बैड्ज का अस्पताल बनाया जायेगा। वहां के लोग जगह भी देने को के लिए तैयार हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर 30 बैड्ज का अस्पताल बनाने की कोई प्रोपोजल गवर्नमैंट के अन्डर कंसीड्रे ान है, यदि है, तो कब तक यह अस्पताल बना देंगे ?

चौधरी भजन लालः अगर हमने कहा है तो जरूर बनायेंगे।

श्री भले रामः अभी बहिन जी ने यह बताया है कि जहां पर 30,000 की आबादी होगी, वहां पर पी0एच0सी0 बनायेंगे। यह बात ठीक है कि हरेक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके यहां पर पी0एच0सी0 बने। हमारे गोहाना में जहां फ्लड्ज सबसे ज्यादा आते हैं, वहां पर मरीज भी ज्यादा होंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह 30,000 की आबादी के हिसाब से पी0एच0सीज0 वगैरा बनायेंगे तो क्या जिन इलाकों में फ्लड्ज वगैरा की वजह से बीमारी ज्यादा फैलती है, उनको प्रैफरैंस देंगे ?

श्रीमती करतार देवीः डेढ़ लाख की आबादी पर एक पी0एच0सी0 के मुकाबले में 30,000 की आबादी पर एक पी0एच0सी0 बनाने की पालिसी के मुताबिक हरेक ब्लाक में अब 4–5 मौडीफाईड पी0एच0सीज0 बन जायेगी। इससे, किसी को हम प्रैफरैंस दें या न दें, सारे इलाके कवर हो जायेंगे।

Setting up of Oil Refinery

***1106. @ Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether the Government is aware of the fact that the Union Government has decided to change the site for setting up of Oil Refinery from near Panipat to some other place; and

(b) if the reply to part(a) above be in affirmative, whether the Government has taken up the matter with the Union Government for not changing the originally proposed site for setting up the said refinery.

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया):

(क) जी नहीं।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भले रामः स्पीकर साहब, यह तो ठीक बात है कि जो आयल रिफाईनरी बन रही है, उसका साईट चेंज नहीं हुआ है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए जमीन एक्वायर करने के लिए कोई कदम सरकार ने उठाये है, और अगर हां, तो क्या कया हैं ? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि उसको बनाने के लिए सरकार की मंजूरी आ गयी है, यदि आ गयी है तो क्या इसके लिए कोई फन्ड अलाट कर दिये गये हैं या नहीं ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, ग्राम बहौली, डड़लाना और खेड़ा–खेड़ी में हमने इसके लिए जीन अभिग्रहण करी है और उसके लिए धारा 4 की अधिसूचना 19 सितम्बर, 1983 को और उसके बाद धारा 6 की अधिसूचना 4 मई, 1985 को इ ा कर दी गयी है।

Mr. Speaker: Question are over.

वर्श 1986–87 का बजट पे ा करना

Mr. Speaker: Now the Finance Minister will present the Budget for the year 1986-87.

वित्त मंत्री (श्री सागर राम गुप्ता): माननीय अध्यक्ष महोदय, और मेरे माननीय साथियां, इस गरिमामय सदन के सामने एक बार फिर उपस्थित होकर हरियाणा सरकार के वर्श 1986–87 के बजट अनुमान पे ा करने का सम्मान पाकर मैं अत्यन्त सौभाग्य का अनुभव कर रहा हूं।

15.00 बजे

विगत वर्श 1985–86 बहुत लम्बे समय तक ऐसी अवधि के रूप में याद किया जाएगा जिसके दौरान हमारे गति ील और युवा प्रधान मंत्री ने एक और स्थायी आर्थिक संत हरचन्द सिंह लौंगोवाल के बीच पंजाब पर ऐतिहासक समझौते पर हस्ताक्षरों का भी साक्षी है। इस समझौते का दे ा और विदे ा दोनों में व्यापक

स्वागत हुआ। इससे इस क्षेत्र में स्थिरता आई है और इससे दे ा के इस भाग में अधिक सद्भाव स्थापित होना चाहिए।

प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के कु ाल नेतृत्व के अधीन पिछले एक वर्श में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा लाए गए नये मूल परिवर्तनों के परिणाम प्राप्त होने प्रारम्भ हो गए हैं। इससे केन्द्रीय राजस्व बढ़ा है और परिणामस्वरूप इनमें से कुछ साधनों में राज्य का तत्संबंधी भाग भी बढ़ गया है।

हरियाणा 1985–86 का आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज माननीय सदस्यों के पास ही है, किन्तु मैं हम लोगों की उपलब्धियों, कठिनाइयों तथा सीमितताओं को संक्षेप में बताना चाहूंगा।

मौसम की विपरीत स्थितियों के होने के बावजूद भी, राज्य में वर्श, 1984–85 में अत्याधिक उत्पादन हुआ है। सरसरी अनुमानों से यह पता चलता है कि राज्य की आय वर्तमान कीमतों पर 10.3 प्रति ात वृद्धि से उस वर्श 4635 करोड़ रूपए हो गई और 1970–71 की कीमतों पर 4.1 प्रति ात वृद्धि से 1562 करोड़ रूपए हो गई। 1970–71 की कीमतों क आधार पर राज्य के घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र में 4.4 प्रति ा की, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8 प्रति ात की और तृतीयक क्षेत्र में 3.3 प्रति ात की वृद्धि हुई। द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रों की ओर विविधता लाने तथा कृशि पर हमारी निर्भरता को कम करने के सरकार के प्रयत्न, 1970–71 से

स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र के अं ा के 1984–85 में 64.8 प्रति ात से घटकर 49.4 प्रति ात तथा द्वितीयक क्षेत्र के अं ा के 15.2 प्रति ात से बढ़कर 19.7 प्रति ात तथा तृतीयक क्षेत्र के 30 प्रति ात से बढ़कर 30.8 प्रति ात हो जाने से स्पश्ट हैं। इस पर भी प्राथमिक क्षेत्र का राज्य के घरेलू उत्पाद में एक बड़ा भाग है जो हमारे राज्य तथा समाज के कृशि प्रधान स्वरूप को द ार्ाता है।

चालू कीमतों के आधार पर राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 1984–85 में 7.7 प्रति ात की वृद्धि हुई और इस समय यहह 3296 रूपए के स्तर तक पहुंच गई। राज्य कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1972–73 आधार) मार्च से दिसम्बर, 1985 तक केवल 5.2 प्रति ात की वृद्धि हुई जबकि अखिल भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्लय सूचकांक में उसी अवधि के दौरान 7.5 प्रति ात की वृद्धि हुई। राज्य सरकार आव यक वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति में संतुलन रखते हुए कीमतों को नियन्त्रण में रख सकी है। हमारे पास 6100 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का जाल है जिसमें से 4500 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 1600 भाहरी क्षेत्रों में। ये अनिवार्यतः समाज के कमजोर वर्गों की सेवा कर रही हैं जिनमें श्रमिक बस्तियां, छात्रावास आदि भाामिल हैं 374 और वि ोश उचित मूल्य की दुकानें, दालों, अभ्यास पुस्तिकाओं, चाय, नमक, मिट्टी का तेल आदि सहित दस

आव यक वस्तुओं की सप्लाई सुनि चत करने की दृश्टि से कार्य कर रही हैं।

पूंजी निर्माण

सरकारी बजट संबंधी अभ्यास, बचत पैदा करके तथा पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए, उनके निवे ा के लिए उपबन्ध करके सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में अधिकतर पूंजी निर्माण को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। 1985–86 के लिए राज्य सरकार के बजट अनुमानों के आर्थिक तथा क्रियात्मक वर्गीकरण से यह प्रकट होता है कि पूंजी निर्माण के लिए सीधी मांग 180 करोड़ रूपय की है। इसके अतिरिक्त निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के पूंजी निर्माण की ओर राज्य का योगदान 156 करोड़ रूपए निर्धारित किया गया था। इस प्रकार चालू वित्त वर्श के दौरान कुल पूंजी निर्माण 336 करोड़ रूपए का अनुमानित है जो गत वर्श के पूंजी निर्माण से 18 प्रति ात अधिक है।

छठी पंचवर्शीय योजना

छठी पंचवर्शीय योजना के दौरान जो 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुई है, राज्य सरकार का योजना खर्च 1576 करोड़ रूपए का था, जो 1800 करोड़ रूपए के मूल अनुमानित योजना परिव्यय से 87 प्रति ात से अधिक कार्यान्न्वयन दि ात करता है। वास्तव में, हमने मूल परिकल्पित योजना निवे ा को ही न केवल

कार्यान्वित बलिक इससे भी अधिक किया होता यदि सरकार द्वारा अप्रत्याि ात मदों पर जैसे, कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, राहत उपायों पर खर्च, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण आव यक हुआ और नियन्त्रित मूल्य प्रणाली द्वारा भाासित मदों की लागत को पूरा करने पर 550 करोड़ रूपए से अधिक खर्च न किया गया होता।

सातवीं पंचवर्शीय योजना

सातवीं पंचवर्शीय योजना, जो 1 अप्रैल, 1985 को आरम्भ हुई, का परिव्यय 2900 करोड़ रूपए रखा गया है। हमारी योजना का सर्वोपरि उद्दे य आर्थिक विकास, समता और सामाजिक न्याय है, जैसा कि सातवीं पंचवर्शीय योजना के नीतिपत्र में परिलक्षित है। राजय के घरेलू उत्पाद में 6 प्रति ात की विकास दर का लक्ष्य है। सबसे अधिक निवे ा सिंचाई और बिजली के मुख्य क्षेत्रों में होगा जो कृशि, उद्योग और वाणिजय के लिए अत्याव यक इन्पुट उपलबघ कराते हैं। 1000 करोड़ रूपए से अधिक का परिव्यय बिजली पर और 585 करोड़ रूपए का परिव्यय सिंचाई पर प्रस्तावित है। परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 200 करोड़ रूपए खर्च करने का प्रस्ताव है। मानवीय साधनों को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने की राश्ट्रीय अग्रता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में लिए लगभग 555 करोड़ रूपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण वि वास है कि केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के मार्ग

द र्न से तथा इस गरिमा ाली सदन के तथा हरियाणा राज्य की जनता के सहयोग से हम सातवीं योजना की अवधि के दौरान राज्य कै सामाजिक आर्थिक विकास की ओर महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।

वार्शिक योजना 1985–86

योजना आयोग के परामर्श से 1985–86 के लिए 480 करोड़ रूपए की वार्शिक योजना नियत की गई थी। दुर्भाग्य से, कुछ प्रत्याशित प्राप्तियों में कमी के कारण, हमें अपनी योजना के खर्चे में थोड़ी कांट छांट करनी पड़ती तथा अब यह 437 करोड़ रूपए, की जा रही है। इनमें से 142 करोड़ रूपए सिंचाई पर, जिसमें बाढ़ नियन्त्रण तथाा सतलुज यमुना योजक नहर भाामिल है। 123 करोड़ रूपए बिजली पर लगभग 78 करोड़ रूपए सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर, लगभग 35 करोड़ रूपए कृशि और संबद्ध सेवाओं पर, लगभग 30 करोड़ रूपऐ परिवहन पर और 10 करोड़ रूपए से अधिक ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाने की संभावना है। योजना निवेश में और कमी न हो इससे बचने के लिए राज्य सरकार ने गैर योजना व्यय को कम करने का निश्चत प्रयास किया है। हम आने वाले वर्शों में भी गैर योजना व्यय के संबध में इसी दृढ़ नीति को अपनाने का प्रस्ताव करते हैं। इससे हम योजना गतिविधियों में निवेश के लिए अधिक राशि बचा सकेंगे।

वार्शिक योजना 1986–87

1986–87 के लिए वार्शिक योजना 525 करोड़ रूपए नियत की गई है। सरकार द्वारा पहले से अपनाई गई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए निवे ा का सबसे बड़ा अं ा सिंचाई तथा बिजली क्षेत्रों में होगा। सिंचाई आदि पर प्रस्तावित परिव्यय 169 करोड़ रूपए से कुछ अधिक है जबकि बिजली पर यह लगभग 163 करोड़ रूपए हैं। सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित परिव्यय 86 करोड़ रूपए से अधिक होगा, कृशि तथा सम्बद्ध सेवाओं पर लगभग 37 करोड़ रूपए, परिवहनन पर 28 करोड़ से अधिक और ग्रामण विकास पर 13 करोड़ रूपए से कुछ अधिक होगा।

सिचंाई

कृशि का वास्तविक आधार सिंचाई है। अतः सतलुज यमुना योजक परियोजना को मिलाकर बड़ी और दरमियानी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन और विकास के लिए 130 करोड़ रूपए से अधिक की रा ि ा की व्यवस्था करना प्रस्तावित है। इससे 30000 हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न होगी। वि व बैंक की सहायता से नहरों के आधुनिकीकरण की वि ोश परियोजना के अन्तर्गत 28 करोड़ रूपए की रा ि ा आगामी वर्श में खर्च करने का प्रस्ताव है। अनुमान है कि इस परियोजना के पूर्ण हो जाने से 2 लाख हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता उत्पन्न

होगी। हरियाणा राज्य लघु सिंचाई तथा नलकूप निगम ने लगभग 15,000 किलोमीटर लम्बे जल मार्ग पक्के किए हैं। लाडवा और नलवी सिंचाई स्कीमें आरम्भ करने की भी व्यवस्था की गई हैं। राज्य के ऊंचे–नीचे क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने के लिए जुई औ सिवी उठान सिंचाई स्कीमें पहले ही पूरी की जा चुकी है तथा जवाहर लाल नेहरू और लोहारू स्कीमों पर कार्य चल रहा है जिन्हें 2.85 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता उत्पन्न करने के लिए बनाया गया है। ऐसे क्षेत्रों में, छिड़काव सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हम सतलुज यमुना योजन नहर के माध्यम से पानी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमान क्षेत्र विकास स्कीम पर अगले वर्श 2 करोड़ रूपए से कुछ अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है।

सतलुज यमुना योजक नहर परियोजना

इस समय सतुलज यमुना योजक नहर परियोजना का वि ोश उल्लेख करना आव यक है जो हमारे लिए अत्याधिक महत्व की है। हमारे प्रधान मंत्री तथा स्वर्गीय सन्त हरचन्द सिंह लौंगोवाल के मध्य हस्ताक्षरित समझौते के भाग के रूप में यह करार किया गया था कि यह परियोजना 15 अगस्त, 1986 तक पूरी कर ली जाएगी।

हम पंजाब सरकार तथा भारत सरकार पर जोर डाल रहे हैं कि वह परियोजना को समय पर पूरा करना सुनि चत

करे। इस परियोजना के लए कुछ म ीनें उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त हम एक सौ दस करोड़ रूपए से अधिक का नकद अं ादान पहले ही कर चुके हैं। पंजाब सरकार तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा इस परियोजना को पूरा करने में बहुत ही गंभीर देरी के दृश्टिगत हमने केन्द्रीय सरकार से प्रभावी हस्तक्षेप, यहां तक कि उन द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन का काम सीधे अपने हाथ में लेने के लिए प्रार्थना की है। हमने केन्द्र सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि वे इस परियोजना के भोश खर्चे को पूरा करें और जब नहर के माध्यम से हरियाणा के क्षेत्र में पानी पहुंचना भाुरू हो जाए तो हमारी हिस्सा उचित रूप से हमसे वसूल कर लें।

बिजली

राज्य सरकार राज्य में बिजली की कमी को दूर करने और पारेशण तथा वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न कर रही है। राज्य में बिजली की आपूर्ति तथा उसकी मांग में बहुत भारी अन्तर रहा है। तथापि आदरणीय प्रधान मंत्री और केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री वसंत साठे क सीधे दखल से हम इस दि ाा में सुधार की आ ाा रखते हैं। अपने हाल ही के राज्य के दौर के दौरान श्री वसंत साठे ने यह घोशणा की है कि बाहरी सहायता से यमुनानगर में 4x210 मैगावाट का थर्मल स्टे ान स्थापित किया जाएगा। उन्होंनै हमें यह भी वि वास दिलाया है कि सातवीं पंचवर्शीय योजना के अन्त तक इस परियोजना के लाभ का सुफल राज्य को प्राप्त होना आरम्भ हो जाएगा। श्री साठे ने

बैरास्यूल, सिंगरौली आदि केन्द्रीय परियोजनाओं से प्रतिदिन अतिरिक्त बीस लाख यूनिट की आपूर्ति के बारे में भी घोशणा की। इससे अप्रैल 1985 और जनवरी 1986 की अवधि के दौरान प्रतिदिन लगातार 9 से 10 लाख यूनिटों की पिछली अनाकाफी आपूर्ति की कमी पूरी हो गई।

वर्श 1986–87 के लिए बिजली के लिए काफी प्रावधान के कारण हमें आ ाा है कि पानीपत के 110 मैगावाट के तीसरे यूनिट का वाणिज्यिक परिचालन ही आरम्भ नही हो जाएगा अपितु 110 मैगावाट का चौथा यूनिट भी पानीपत में अगले वर्श के मध्य तक चालू हो जाएगा। पि चमी यमुना नहर पनबिजली परियोजना के अधीन मार्च 1986 से पहले आठ–आठ मैगावाट के दो यूनिट चालू हो जाएंगे और ऐसे दो और यूनिट आगामी वित्त वर्श में चालू हो जाएंगे। पानीपत के 210 मैगावाट के थर्मल यूनिट के ठोस प्रगति प्राप्त किए जाने की भी संभावना है। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री ने हमें पानीपत में 210 मैगावाटा का एक और यूनिट स्थापित करने में भी सहायता देने का वि वास दिलाया है। हम ने भारत सरकार से हरियाणा में परमाणु बिजली यूनिट स्थापित करने की भी प्रार्थना की है। इन परियोजनाओं के फलीभूत होने पर हम राज्य के कृशि, उद्योग, वाणिज्य तथा घरेलू क्षेत्रों में बिजली की आव यकता को और अधिक समुतिच रूप से पूरा करने की आ ा कर सकेंगे।

कृशि

सिंचाई तथा बिजली के प्रावधान के अतिरिक्त जो कि कृशि की रीढ़ है वर्श 1986–87 के दौरान सीधे कृशि के लिए काफी प्रावधान का प्रस्ताव है। इसी प्रकार वर्तमान किस्मों के अधीन 27.75 लाख हैक्टेयर भूमि लाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार वर्तमान वर्श के 1.46 लाख क्विंटल प्रमाणीकृत बीजों और 3.86 लाख टन उर्वरक के मुकाबले में अगले साल राज्य में दो लाख क्विंटल प्रमाणीकृत बीज और चार लाख टन से अधिक उर्वरक की खपत की संभावना है। जबकि चालू वर्श के दौरान, खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 75 लाख टन से कुछ अधिक होनेक की आ ाा है, आगामी वर्श इस उत्पादन के लगभग 77.65 लाख टन तक हो जाने की संभावना है। इसी प्रकार, कपास का उत्पादन 8 से 8.3 लाख गांठे और तिलहनों का उत्पादन 1.85 लाख टन से बढ़ कर 2.62 लाख टन हो जाने की संभावना है।

हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम द्वारा आगामी वर्श लगभग 80,000 मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता बढ़ाने की संभावना है। हरियाणा भूमि सुधार और विकास निगम द्वारा 9000 हैक्टेयर कल्लर भूमि को सुधारने और 5600 हैक्टेयर ऊंची नीची भूमि का समतल बनाने की संभावना है ताकि इसे का त के योग्य बनाया जा सके। हरियाणा बीज विकास निगम द्वारा वर्श 1986–87 के दौरान 1.7 लाख क्विंटल उन्नत बीज वितरित करने की आ ाा है, जबकि हरियाणा राज्य लघु कृशि विपणन बोर्ड द्वारा 7 विनियमित मण्डियों, 29 उप मण्डी यार्डो और 30 खरीद केन्द्रों को विकसित

करने की संभावना है। यह वर्श 1986–87 के दौरान लगभग 88000 मीट्रिक टन की भण्डारण क्षमता को भी बढ़ायेगा।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास तथा गरीबी को कम करना ये दोहरे उद्दे य समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राश्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों के हैं। इन स्कीमों को आगामी वर्श के दौरान और अधिक तेजी से चलाने का प्रस्ताव है। मेवात क्षेत्र का व्यापक ढंग से विकास करने के लिए, आगामी वर्श के दौरान 2.5 करोड़ रूपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

खाद्य तथा पूर्ति

राज्य की खाद्यान्न खरीद एजेन्सियों ने, जिनमें खाद्य तथा पूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम भाामिल हैं रबी, 1985 के दौरान 19.6 लाख टन गेहूं और खरीफ, 1985 के दौरान 9.6 लाख टन चावल की रिकार्ड खरीद की है। निस्सन्देह, हमारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय खाद्य निगम द्वारा दी गई सहायता के लिए हम उनके आभारी हैं।

प ाुपालन

प ाुपालन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वर्श 1986–87 के दौरान 40 नयी प ाु चिकित्सा डिस्पैंसरियां खोलने 30 डिस्पैंसरियों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें हस्पताल बनाने और एक पालिक्लीनिक स्थापित करने का प्रस्ताव है। 5000 परिवारों को मुर्गीपालन, सुअरपालन, भेड़ और संकर बछड़ा प्रजनन हेतु सहायता देने की स्कीम में भाामिल किये जाने की संभावना है।

मछली पालन

मछली पालन कार्यक्रम भी पिछले थोडें समय से राज्य में अपनी जड़ मजबूत कर रहा हैं। राज्य में पहले से ही कार्यरत 4 मछली पालक विकास ऐजन्सियों के अतिरिक्त अगले वर्श के दौरान एक और ऐसी एजेन्सी स्थापित करने का प्रस्ताव हैं। अगले वर्श मछली उत्पादन 15000 टन तक हो जाने की संभावना हैं।

यद्यपि अनुपाततः हमारे क्षेंत्र की एक छोटी सी प्रति ातता वनों के अन्तर्गत हैं, फिर भी हमारे प्रयास स्पश्टतः प्रभाव ाली रहे हैं। वन रोपण की राश्ट्रीय नीति के अनुसार वनों को बढ़ाने, वनना ान को रोकने और एकीकृत ढंग से वाटर ौड़ो की व्यवस्था करने के भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। वि व बैंक, सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना पहले से ही प्रगति पर हैं। वर्श 1986–87 के दौरान, वन के अधीन अतिरिक्त 22000 हैक्टेयर भूमि को लाने तथा 38 लाख नये पौधे लगाने का प्रस्ताव हैं। इससे 50 लाख श्रम दिवसो के रोजगार अवसर भी पैदा हो

जायेंगे। वर्श 1986–87 के दौरान वानिकील और वन्य प्राणी संरक्षण पर परिव्यय के 12 करोड़ रूपये से कुछ अधिक किए जाने का प्रस्ताव हैं।

सहकारिता

सहकारिता अभियान ने राज्य में, वि ोशकर ग्रामीण क्षेत्र में, सामजिक आर्थिक द्वारा आगामी वर्श में 60 करोड़ रूपये की ऋण रा ि ा के वितरित किये जाने का अनुमान हैं। हैफेड आगमी वर्श के दौरान दो और चावल मिलों और कुछ अन्य कृशि आधरित परियोजओं को स्थापित करने का प्रस्ताव हैं।

उद्योग

हरियाणा का दे ा के औद्योगिक मानचित्र पर एक वि ोश स्थान हैं। आगे भी अपने स्थिति को बनाए रखने के विचार से और परम्परागत क्षेत्रों से नये क्षेत्रों में विविधीकरण के विचार से, हारटरोन के माध्यम से बहुत सी स्कीमें अपना ली गई हैं। राज्य में इलैक्ट्रोनिक उद्योग के विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। राज्य में कंप्यूटरों का जला बिछाने का भी प्रस्ताव हैं। पंचकूला में भारत इलैक्ट्रोनिकी लिमिटेड काम्पलैक्स और गुड़गांव के निकट इलैक्ट्रोनिक भारत गांव ने अपना रूप लेना भ्रुरू कर दिया हैं।

करनाल तेल ाोधक परियोजना का वि ोश रूप से उल्लेख करने की आव यकता हैं जो केन्द्र सरकार का अनुमोदित

कार्यक्रम हैं। हम समझते हैं कि इस स्कीम के लिए वित्तसाधन लगभग 1300 करोड़ रूपए होगी। हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया हैं कि वह हमें इस परियोजना में इक्यूटी हिस्सा दें, जिसके एक संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना के रूप में स्थापित किए जाने की सम्भावना हैं। मुझे पूर्ण आ ाा हैं कि यह परियोजना राज्य के आगामी उद्योगीकरण और आर्थिक विकास को अधिक गति प्रदान करेगी।

ग्रामीण उद्योगीकरण स्कीम के अधीन, वर्श 1986–87 के दौरान 4000 से अधिक यूनिट स्थापित किए जांएगे जो 12000 से अधिक व्यक्तियों की रोजगार प्रदान करेंगे।

ऊर्जा के गैरपरम्परागत विकास के लिए एक स्कीम भी चालू हैं। हिसार और करनाल के 2 और विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भाुरू कर दिया गया हैं। हरियाणा कृशि वि वविद्यालय हिसार में एक दूरस्थ आभास केन्द्र की भी स्थपना की जा रही हैं। उद्योग, औद्योगिक और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर अगामी वर्श के दौरान लगभग 12 करोड़ रूपए की रा ि ा खर्च किए जाने का प्रस्ताव हैं

सड़के

हरियाणा दे ा में पहला राज्य हैं जहां प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों के साथ जोड़ दिया गया हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान 1834 किलोमीटर सड़को को बनाने का प्रस्ताव हैं जिस

पर 107 करोड़ रूपए का परिव्यय होगा। वर्श 1986–87 के लिए लक्ष्य 247 किलोमीटर सड़को का हैं जिस पर 14.5 करोड़ रूपये का परिव्यय होगा।

परिवहन

हरियाणा रोडवेज अपने कार्यचालन में अब भी अग्रगण्य हैं। हाल ही में इस ने वर्श 1984 के राश्ट्रीय उत्पादी पुरस्कारों में दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया था। सड़क परिवहन प्रणाली का और विस्तार का इरादा हैं और अगले वर्श 150 अतिरिक्त बसें और बढ़ा दी जायेंगी। हिसार में बस अड्डे के भवन को गिल्ड आफ प्रैक्टाइजिंग आर्कीटैक्ट्स, नई दिल्ली द्वारा प्रथम पुरस्कार दिया गया हैं।

ि ाक्षा

हम ि ाक्षा को लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। लड़कियों के लिए 100 स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव हैं। हम इस वर्श के अन्त तक 6–11 आयु वर्ग में भातप्रति ात दाखिले की लक्ष्य–प्राप्ति कर लिए जाने की आ ाा रखते हैं। प्रौढ़ अनपढ़ व्यक्तियों के लाभार्थ 1986–87 के दौरान 100 प्राइमरी स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें मिडल स्कूल बनाने का प्रस्ताव हैं। इस समय राज्य में, 5.761 प्रौढ़ ि ाक्षा केन्द्र और 4387 अनौपचारिक ि ाक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

उच्चतर ि ाक्षा के संदर्भ में गैर सरकारी कालेजों के ि ाक्षण अमले को वेतन के तिवरण के सम्बनध में सरकार द्वारा हाल ही में लिय निर्णय वि ोश रूप से उल्लेखनीय हैं। उनको वेतन की अदायगी बैंकों के माध्यम से किए जाने की मांग लम्बे समय से की जा रही थी। जैसे कि 20 फरवरी, 1986 को सदन में माननयी मुख्य मंत्री द्वारा घोशित किया गया था, अनेक बार विचार विम र्ा करने और अन्तिम रूप से इन कालिजों की प्रबन्ध समिति, उनके प्रिसिपलों और ि ाक्षण तथा गैर–ि ाक्षण अमले के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विम र्ा करने के प चात राज्य सरकार ने फैसला किया हैं कि प्राइवेट कालेजों के ि ाक्षण तथा गैर ि ाक्षण अमले को 1–4–1986 से वेतन की बावजूद इसके कि ऐसे प्रबन्ध किए जा रहे हैं, हम 1985–86 के लिए इन कालेजों देंगे। इस से सम्बन्धित अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। प्रथम अप्रैल, 1986 से चालू करने के लिए इस स्कीम के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा हैं जैसा कि घोशित भी किया जा चुका हैं।

सरकार का प्रस्ताव हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान स्कूल भवनों का रख–रखाव करलने और उन्हें बढ़ाने की ओर वि ोश ध्यान दिया जाए। चालू वर्श में ग्रामीण स्कूल भवनों में 1110 और कमरों की वृद्धि की गई हैं। राज्य में, पर्याप्त निधियों की भी व्यवस्था की जा रही हैं। राज्य स्कूल ि ाक्षा बोर्ड के लिए भिवानी में एक नए काम्पलैक्स की स्थपना की गई हैं। इस नए

भवन की स्थपना से बोर्ड अधिक प्रभाव ाली ढंग से कार्य कर सकेगा और राज्य में स्कूल ि ाक्षा की बेहतर देखभाल भी कर सकेगा।

स्वास्थ्य

अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग का स्वास्थ्य सुधारने और उन्हें चिकित्सा सुविधांए जुटाने के विचार से , 1986–87 के दौरान उप–स्वास्थ्य केन्द्र, 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10 सममुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने कका प्रस्ताव हैं। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन कुरूक्षेत्र और रोहतक के अलावा दो और जिलों को इसके अधीन लाने का प्रस्ताव हैं। हम परिवार कल्याण के राश्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन निरन्तर वि ि ाश्टता प्राप्त करते रहे हैं और राज्य ने निरन्तर तीसरी बार राश्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हैं। 1986–87 के लिए 1.5 लाख बंधीकरण का लक्ष्य नियत किया गया हैं।

मेडिकल कालेज रोहतक में एक हस्पताल इंजीनियरिंग संस्थान ने कार्य करना भुरू कर दिया हैं। सातवीं योजना के दौरान रोहतक में आर्थोपैडिवस, ट्रामाटोलॉजी और पुनर्वास के एक संस्थान की स्थापना का भी प्रस्ताव हैं। अन्य पेचीदा तथा संवेदन ाील सुविधएं जुटाने का भी प्रस्ताव हैं। स्वास्थ्य तथा चिकित्सा ि ाक्षा सेवाओं के लिए सांतवी योजना के दौरान 78 करोड़ रूपए से भी अधिक के परिव्यय का प्रस्ताव हैं जिसमें से 12

करोड़ रूपए से भी अधिक रा ि । 1986–87 के दौरान खर्च की जाएगी।

जन स्वास्थ्य

वर्श 1986–87 में जल सप्लाई और मल निकसा स्कीमों के लिये रखे गए 26 करोड़ रूपए से कुछ अधिक परिव्यय से हम वर्श 1986–87 के दौरान 310 और गांवों में नल द्वारा जल की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखते हैं। तुरन्त ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम की भात प्रति ात केन्द्र चालित स्कीम के अन्तर्गत इस वर्श के अन्त तक अन्य 200 गांवों को इसके अधीन लाया जयेगा। 4252 समस्या गांवों को आगमी वर्श के अन्त तक नल द्वारा जल सप्लाई स्कीमों के अधीन लाया जाएगा।

आवास

आवास की अत्याधिक आव यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य आवास बोर्ड द्वारा 47.5 करोड़ रूपये के परिव्यय से सातवीं योजनावधि के दौरान 15,000 अतिरिक्त मकान बनाने का प्रस्ताव है। नयी आवास की अध्यक्षता की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के समाधान के लिए आवास सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर विभागीय तालमेल समिति बनाई गई है। हम, समाज के कमजोर वर्गो के उन सदस्यों को आवास सुविधाएं देने सम्बन्धी स्कीम पर भी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन प्लाट अलाट किए जा चुके हैं।

श्रम तथा रोजगार

1985–86 का वर्श, राज्य में बिना किसी प्रकार की तालाबन्दी के व्यतीत हो गया है, इससे राज्य में सुखद औद्योगिक सम्बन्धों का पता चलता है। लोगों की और अधिक प्रभाव ाली ढंग से सेवा करने के लिए राजगार केन्द्र के कार्यों को कम्प्यूटरयुक्त करने हेतु एक कार्यक्रम भुरू किया गया है।

भाहरी विकास

राज्य सरकार मुख्यतः हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से भाहरी विकास कार्यक्रम को तेज कर रही है। राश्ट्रीय राजधानी प्रदे ा का व्यापक विकास भी हाथ में है।

योजना का विकेन्द्रीयकरण

योजना प्रक्रिया को और अधिक सार्थक बनाने के लिए और नीचे से उसे अधिक प्रोत्साहित करने के लिए, वर्श 1986–87 के दौरान प्रत्येक जिले में जिला योजनाा यूनिटों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण

सामाजिक तथा भाारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और समाज के कमजोर वर्गों के सदस्यों का उत्थान सदैव सरकार के एक नैतिक दायित्व के तौर पर रहा है। वि ोश संघटक योजना के अधीन वर्श 1986–87 के लिए परिव्यय 29.63 करोड़

रूपये प्रस्तावित है। वर्श 1986–87 के दौरान उनकी ि ाक्षा को प्रोत्साहित करने, आवास सुविधाओं को बढ़ाने, हरिजन बस्तियों को सुधारने, कार्य भाुरू करने के लिए उन्हें कु ालता प्रदान करने के लिए स्कीमें, लगभग 12 करोड़ रूपये की कुल लागत से कार्यान्वित की जायेंगी। हरियाणा हरिजन कलयाण निगम, राज्य सरकाार से हिस्सापूंजी और कर्ज की सहायता से और बैंकों के सहयोग से आर्थिक सहायता, सीमान्त राि ा और सीधे कर्ज सम्बन्धी स्कीम चला रहा है। हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम भी उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहा है। 40 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से, वर्श 1986–87 के दौरान 3 लाख से अधिक बच्चों और गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं को लाभ देने का प्रस्ताव है।

पर्यटन

हरियाणा ने पर्यटन क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। हम अपने अतिथियों का पूरा ध्यान रखते आ रहे हैं। बल्लभगढ़ मे ंएक नया पर्यटक काम्पलैक्स हाल ही में खोला गया है और नरवाना और अम्बाला में इनके जल्दी ही चालू किए जाने की सम्भावना है। कुरूक्षेत्र में यात्री निवास और युवा होस्टल तथा बहादुरगढ़ में एक नया पर्यटक काम्पलैक्स भाीघ्र ही खोलने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना के दौरान पर्यटन पर 11 करोड़ रूपए तथा आगामी वर्श के दौरान 1.38 करोड़ रूपए का परिव्यय होगा।

स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

राज्य सरकार स्वतन्त्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की आव यकताओं के बारे में पूर्णतः संवेदन ाील और कार्य ाील है। 30,000 भूतपूर्व सैनिकों ो स्व–नियोजन के लिए 30 करोड़ रूपए की ऋण सहायता दी जाएगी। पैक्ससैम (भूतपूर्व सैनिकों को स्व–नियोजन स्कीम के लिए तैयार करना) भिवानी और महेन्द्रगए जिलों में चालू है तथा आगामी वर्श में 4 और जिलों मे इसका विस्तार कर दिया जाएगा। 15 अगस्त, 1985 से स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन् ान की दर 100 रूपए प्रतिमास से बढ़ाकर 200 रूपए प्रतिमास कर दी गई है।

20 सूत्री कार्यक्रम

20 सूत्री कार्यक्रम को जिसमें राज्य के लगभग सभी महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक गतिविधियां भाामिल हैं, हमारी योजना में भली भान्ति गूंध दिया गया है तथा कुल पूंजी का लगभग 70 से 80 प्रति ात परिव्यय इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किया जा रहा है। आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल, 1985 तथा जनवरी 1986 के बीच 52,000 से अधिक परिवारों को जिनमें 32,000 से अधिक अनुसूचित जातियों के हैं, सहायता दी गई है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 32,000 से कुछ अधिक लाभ प्राप्त करने वालों को इस अवधि में दी गई सहायता तथा बांटा गया कर्ज क्रम ा 4.15 करोड़ रूपए

और 9.23 करोड़ रूपए का था। राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन 9.75 लाख श्रम दिनों के रोजगार अवसर जुटाए गए हैं। गन्दी बस्ती सुधार स्कीमों के अधीन लगभग 62,000 गन्दी बस्ती जनसंख्या भाामिल की गई है। इस अवधि के दौरान 1500 से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाए गए हैं तथा 1600 से अधिक बायोगेस संयन्त्र लगाए गए है। 7500 से अधिक पंम्पिग सैटों को बिजली दी गई है।

प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत

1984–85 के दौरान राज्य के 9 जिलों मे सूखा पड़ा था और फसलें बुरी तरह से नश्ट हो गई थीं। खरीफ, 1985 के दौरान हिसार, सिरसा, जींद, अम्बाला, कुरूक्षेत्र, गुड़गांव, रोहतक के जिलों में बहुत अधिक बाढ़ आई थी। सम्पति और मनुश्य तथा प ा जीवन के नुकसान के अतिरिक्त 25 करोड़ रूपये से अधिक की फसलौं के नुकसान का अनुमान लगाया गया था। हमने भारत सरकार से 39 करोड़ रूपए से अधिक की राहत मांगी है और उनके निर्णय की प्रमीक्षा की जा रही हैं। भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव और रोहतक जिलों से सूखे के कारण चारे की अत्याधिक कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। किसानों को राहत देने के लिए चारे और बीज की तकावी के रूप में वितरण के लिए 1.4 करोड़ रूपए मंजूर किए गए है। अप्रत्याि ात प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य और नागरिक दोनों पर भार डाला है।

1985–86 के सं ाोधित अनुमान

सं ाोधित अनुमानों के अनुसार वर्श 1985–86 के 114.32 करोड़ रूपए के बजट के घाटे के मुकाबले में 0.41 करोड़ रूपए के बहुत थोड़े से घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। अतिरिक्त साधन जुटाकर और योजना पक्ष सहित खर्चे को कम करके इस पूर्व अनुमानित कमी को पूरा करना संभव हो सका है। हमारे इस कार्य में राजस्व इकट्ठा करने तथा छोटी बचतें इकट्ठी करने में अत्याधिक वृद्धि से भी हमें सहायता मिली है। वर्श के लिए सं ाोधित योजना खर्च लगभग 437 करोड़ रूपए होगा।

1986–87 के बजट अनुमान तथा वार्शिक योजना

श्रीमन, अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस गरिमा ाली सदन के सामने 1986–87 के लिए हरियाणा सरकार के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। निम्नलिखित सारणी में 1985–86 के सं ाोधित अनुमानों तथा 1986–87 के बजट अनुमानों के फलस्वरूप राज्य की वित्तीय स्थिति का संक्षेप में विवरण दिया गया है:–

(करोड़ रूपयों में)

क्रमांक	संघटक	बजट अनुमान 1985–86	सं ाोधित अनुमान 1985–86	बजट अनुमान 1986–87

1	अथ भोश			
क	महालेखाकार के अनुसार	(-)63.80	(-)47.72	(+)43.01
ख	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(-)91.53	(-)91.14	(-)0.41
2	राजस्व लेखा			
	प्राप्तियां	901.27	959.38	1040.14
	खर्च	828.77	843.73	907.16
	अधि ोश	(+)72.50	(+)115.65	(+)132.98
3	पूंजीगत खर्च			
	(निवल)	184.15	208.18	186.65
4	लोक ऋण			
	लिया गया ऋण	700.45	924.03	749.10
	अदायगी	615.93	645.82	626.71
	निवल	(+)	(+)278.21	(+)122.39
5	कर्जे पे ागियां			

	पे ागियां	147.53	152.66	166.45
	वसूलियां	22.87	18.34	30.40
	निवल	(-)124.66	(-)134.32	(-)136.05
6	अन्तर्राज्यीय			
	निपटान			
7	आकस्मिक निधि			
	निवल			
8	अनिधिक ऋण			
	निवल	(+)29.95	(+)32.43	(+)37.41
9	निक्षेप तथा पे ागियां आदि			
	निवल	(+)95.05	(+)2.94	(+)2.19
10	प्रेशण (निवल)	(+)4.00	(+)4.00	(+)1.00
11	वर्श का इति ोश			
क	महालेखाकार के अनुसार			

ख	भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार	(-)86.59	(+)43.01	(+)16.28
		(-)114.32	(-)0.41	(-)27.14

1986–87 के उपर्युक्त अनुमानों तथा प्रक्षेपों की अनन्य वि ोशताओं को वि ोश रूप से बताने की आव यकता हैं। राजय के राजस्व अधि ोश में, 1985–86 के सं ाोधित अनुमानों तथा 1986–87 के बजट अनुमानों दोनों में ही उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह राज्य के विभागों द्वारा त्वरित राजस्व वसूली प्रयास को द ार्ाता है। यह सरकार की राजस्व खर्च के नियन्त्रण की इच्छा को भी प्रद ि र्ात करता है। यह बहुत ही संतोध का विशय है क 1986–87 के दौरान हमारा योजना निवे ा 525 करोड़ रूपए रखा गया है जबकि चालू वर्श के दौरान सं ााधित योजना खर्च 437 करोड़ रूपए होगा। 1985–86 तथा 1986–87 के बीच इस बढ़ौतरी में सबसे अधिक वृद्धि सिंचाई और बिजली के मुख्य क्षेत्रों में है। उनका परिव्यय सिंचाई पर 142 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 169 करोड़ रूपए और जिबजली पर 123 करोड़ रूपए से 163 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इसी प्रकार सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय अगले वर्श 78 करोड़ से बढ़कर लगभग 87 करोड़ रूपए होने जा रहा है। मुझे वि वास है कि मेरे सभी साथियों के सहयोग से और हमारे मुख्य मंत्री जी के मार्गद र्ान से आने वाले वर्शों में योजना तथा गैर योजना खर्च के बीच अधिक अनुकूल अनुपात संभव होगा।

1986–87 के पूर्व वर्णित बजट अनुमानों में 31 मार्च, 1987 को 27.14 करोड़ रूपए का घाटा होने की संभावना मानी गई है। हमने पहली ही सतलुज यमुना योजक नहर की भोश लागत के लए पूरी रा ि ा देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है। यदि यह हो जाता है तो इस घाटे को पूरी तरह समाप्त करना संभव हो जाएगा। मुझे आ ाा है कि कन्द्रीय सरकार हमारी परिस्थितियों को समझेगी और हमें आव यकत सुविधा प्रदान करेगी।

परेशण–कर

परेशण–कर लगाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास काफी समय से लम्बित पड़ा है। वास्तव में इसको भारत सरकार को अपने वायदे के अनुसार काफी पहले लगाया जाना चाहिए था। मुझे आ ाा है कि अब इसे अधिक से अधिक 1 अप्रैल, 1986 तक तो लागू कर ही दिया जाएगा। यदि यह हो जाता है तो इससे लगभग 50 करोड़ रूपए का अतिरिक्त राजस्व अगले वर्श प्राप्त हो सकता है। इससे 1986–87 के लिए और बड़ी योजना कार्यान्वित करना संभव होगा। वास्तव में योजना आयोग की गोश्ठियों में योजना के लिए हमारी निवे ा आव यकताओं को लगभग 600 करोड़ रूपया आंका गया था।

किसानों, व्यापार तथा उद्योग को रियायत

जहां एक ओर हमने अनुत्पादी खर्च पर कठोर नियन्त्रण किया है, हम किसानों, व्यापार तथा उद्योग की उचित आव यकताओं के प्रति भी संवेदन ील रहे हैं। ट्रैक्टरों पर बिक्री कर की दर 4 प्रति ात के कम स्तर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए रखी गई है ताकि इन्हें किसानों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जा सके। राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए, बिक्रकी कर स्थगन योजना बनाई गई है। बर्तनों की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर 10 प्रति ात से 4 प्रति ात उस स्थिति में भी घटा दी गई है जहां ये गैर–पंजीकृत व्यापरियों को भी की जाती है। यह सुविधा 1–11–1985 से 31–3–1986 तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है तथा इसके बाद पुनरीक्षित की जाएगी। इसी प्रकार चने की दाल की अन्तर्राज्यीय बिक्री दर कन्द्रीय विक्रय कर की दर 1–11–1985 से 31–3–1986 तक की अवधि के लिए 4 प्रति ात से घटाकर 2 प्रति ात कर दी गई है, तथा स्थिति इसके बाद पुनरीक्षित की जाएगी।

सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को रियायतें तथा सुविधाएं

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 1–4–1979 से पहले तथा उसके बाद सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के पें ान फार्मूले में असंगति को दूर करने का निर्णय लिया है।

सैनिकों को वीरता पुरस्कार

उन सैनिकों को, जो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि के प्राप्तकर्ता हैं, वीरता पुरस्कार के लिए एक सं ाोधित योजना बनाई गई है तथा नकद लाभ पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 20 लाख रूपए का अतिरिक्त दायित्व पड़ेगा।

राजकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए व्यक्तिक पदोन्नति स्कीम का प्रारम्भ किया जाना

वि वविद्यालय अनुदान आयोग के सुझाव महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के लिए वयक्तिक पदोन्नति से सम्बन्धित स्कीम का प्रारम्भ किया जाना सरकार के विचाराधीन था। अब इस स्कीम को मुख्यतः वि वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रस्ताव के अनुसार प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। साथ–साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि व्यक्तिक पदोन्नति स्कीम के अधीन ऐसे उच्चतर पदों की मात्रा संवर्ग संख्या के 20 प्रति ात तक उपलब्ध होगी तथा सेवा में 12 वर्श पूरे करने से पहले उपलब्ध नहीं होगी। ये दो निर्णय अर्थात बैंकों के माध्यम से गैर सरकारी महाविद्यालयों के ि ाक्षण तथा गेर–ि ाक्षण अमले को वेतन का भुगतान करने तथा राजकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए व्यक्तिक पदोन्नति स्कीम के प्रारम्भ किए जाने से न केवल उनके जीवन

स्तर में सुधार होगा बल्कि इससे विद्यार्थियों का प्र ाक्षण भी बेहतर होगा।

हरियाणा सड़क परिवहन की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा स्कीम का आरम्भ किया जाना

हरियाणा सड़क परिवहन की बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों या उनके उत्तरजीवियों को सड़क दुर्घटनाओं में (उनके मरने की दुर्भाग्यपूर्ण द ाा में) पर्याप्त रूप से मुआवजा देने की दृश्टि से 1–4–1986 से इन यात्रियों के व्यक्तिक बीमे के लिए स्कीम भाुरू किए जाने का प्रस्ताव है। यह मुख्यतः हवाई उड़ानों में यात्रियों के लिए बीमा स्कीम के अनुरूप होगी।

ग्राम उत्थान स्कीमें

वास्तविक भारत अब भी गांवों में रहता है। बहुत सी सामाजिक आर्थिक स्कीमें आरम्भ की गई हैं और इनसे गांवों की उत्पादकता तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है। फिर भी, यह महसूस किया गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्कला बाद स्वैच्छिक सेवा और सामाजिक जागरूकता का जो उत्साह पैदा हुआ था, वह अब लुप्त सा हो रहा है। ग्रामीणों में अपना वातावरण और अपने जीवन की द ााओं को सुधारने के लिए उत्साह पैदा करने हेतु सरकार ने आगामी वित्त वर्श से ग्राम उन्नयन स्कीम प्रारम्भ करने का नि चय किया है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रति वर्श प्रत्येक जिले में सामाजिक आर्थिक विकास में

अपने उत्कृश्ट कार्यों के लिए 3 गांवों का चयन किया जाएगा। अपने अपने कार्यो के आधार पर इन 3 गांवों में से प्रत्येक को या तो एक लाख रूपए का प्रथम पुरस्कार या 50000 रूपए का द्वितीय पुरस्कार अथवा 25,000 रूपए का तृतीय पुरस्कार पाने का हक होगा। गांव के कार्यों का मूल्यांकन करने का मापदण्ड अन्य बातों के साथ साथ परिवार कल्याण के प्रति प्रयास, प्रौढ़ तथा अनौपचारिक ि ाक्षा का प्रसार, विद्यालयों के लिए पात्र बच्चों का प्रवे ा और उपस्थिति में उनकी नियमितत, लघु बचत के प्रति योगदान ग्राम विवादों में कमी, स्वच्छता तथा सफाई, वन–संवर्धन, कृशि उत्पाद में वृद्धि आधुनिक तकनीकों को अपनाना और कृशि उत्पादन के लिए साधन आदि का होगा। प्रतयेक जिले के लिए जिले के उपयुक्त की अध्यक्षता में एक चयन समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव हैं। पुरस्कार रा ि ा नकद दी जाएगी और उसका उपयोग ग्रामवासियों द्वारा गांव के और अधिक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए किया जाना चाहिए। मुझे पूरा वि वास है कि इस नई स्कीम से हमारे गांव वालों को अधिक स्वास्थ्यकर और अधिक मैत्रीपूर्ण जीवन के प्रति उत्साह मिलेगा। चूंकि गांवों को पुरस्कार सौंदर्यपरक और मांगलिक लक्षणों के आधार पर दिए जाएंगे, इसलिए इस स्कीम का नाम सुलक्षणा स्कीम देने का प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा भत्ता स्कीम

सरकारी कर्मचारियों की ओर से यह लगातार मांग रही है कि उन्हें चिकित्सा पर पहले धन खर्च करने और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नियत चिकितसीय भत्ता दिया जाना चाहिए। सरकार ने सम्पूर्ण मामले पर विचार किया है और यह निर्ण लिया है कि पहली मार्च 1986 से चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति की स्कीम उपलब्ध नहीं होगी किन्तु, राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके द्वारा आउटडोर चिकित्सा पर हुए खर्च कि प्रतिपूर्ति करने के लिए आगामी वित्त वर्श से 100 रूपए वार्शिक भत्ते का भूगतान किया जाएगा। यह सभी वर्गों के कर्मचारियों को समान रूप से प्रति वर्श अक्तूबर मास के वेतन के साथ दिया जाएगा।

सरकार इस बात के लिए अधिक इच्छुक है कि चिकित्सीय खर्चों की प्रतिपूर्ति की बजाय स्वस्थ बने रहने की भावना में बढ़ौतरी हो। स्वयं सरकारी कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों, दोनों को भाारीरिक तथा मानसिक रूप से बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देने की दृश्टि से, सरकार योग प्र ाक्षण के लिए एक विस्तृत स्कीम भाुरू कर रही है। खेलकूद विभाग को इस सम्बन्ध में एक स्कीम बनाने के लिए कहा गया है।

दोहरे कार्य के लिए वि ोश भत्ता

चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि जहां वे दोहरा काम करते हैं, उन्हें कुछ मुआवजे के रूप में लाभी दिया जाए। सरकार ने इस मामले पर विचार किया है और नि चय किया है कि सरकारी कार्यालयों में 1–4–86 से सेवादार एवं चौकीदार, सेवादार एवं माली तथा चौकीदार एवं माली के दोहरे पदों को धारण करने वाले कर्मचारी 30 रूपये प्रतिमास वि ोश भत्ता लेने के हकदार होंगे। इस वि ोश भत्ते की मंजूरी से वे अधिसमय भत्ते के हकदार नहीं रहेंगे।

सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

सरकार अपने कर्मचारियों की कठिनाइयों और समस्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक है। फिर भी, हमने कोई नए प्रोत्साहन या लाभ देने का प्रस्ताव नहीं किया है, क्योंकि हम केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की प्रति ाा कर रहे हैं। हम समझते हैं कि उक्त आयोग, अपनी रिपोर्ट तथा सिफारि ों आगामी कुछ महीनों में केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे तथा अन्य लाभ का, उन सिफारि ाों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रका ा में हमारा पुनः परीक्षण करने का प्रस्ताव है।

राज्य की अर्थोपाय की स्थिति

खर्च में और अधिक वितीय अनु ाासन तथा औचित्य लाने के उद्दे य से केन्द्रीय सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरड्राफ्ट की वह सुविधा वापस ले ली हैं, जिसका उपयोग राज्यों द्वारा आकस्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाता था। अपने सीमित साधनों के बावजद भी हम पर लगाए गए कठोर प्रतिबन्धों के अन्तर्गत हमने सारा साल अपनी अर्थोपाय की स्थिति को और अधिक सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के उद्दे य से यह नि चय किया गया है कि प्रथम अप्रैल, 1986 से मण्डी समिति द्वारा संगृहीत मण्डी फीसों की प्राप्तियां तथा उनके विरूद्ध खर्च राज्य कोशों के माध्यम से हुआ करेगा। परन्तु, इससे इन साधनों पर राज्य द्वारा बजटीय नियन्त्रण का आ ाय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य रूप से बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री सबसे कम सत्कार योग्य होता है और बजट भाशण स्पश्ट कारणों से एक भयावह दस्तावेज समझ जाता है। 1986–87 का बजट एक महत्वपूर्ण अपवाद रहेगा। हमने समाज के किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा है।

भाशण समाप्त करने से पूर्व मैं वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इन अनुमानों को तैयार करने में अमूल्य सहायता दी है। इस संबन्ध में सहायता देने के लिए महालेखाकार हरियाणा का तथा इन दस्तावेजों को समय पर छापने के लिए संघीय क्षेत्र प्र ाासन और हरियाणा मुद्रणालय का भी धन्यवादी हूं।

महोदय, इन भाब्दों के साथ अब मैं वर्श 1986–87 के बजट अनुमानों को इस गरिमा ाली सदन के विचार तथा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द।

श्री अध्यक्षः अब हाउस, कल 26 फरवरी, 1986 प्रातः 9.30 बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है।

15.42 बजे

(तत्प चात् सदन बुधवार दिनांक 26–2–1986 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)